

सुप्रभातम्

सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है।

तीन बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त पूंजी जारी : महंत

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। असम के तीन बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री केशव महंत ने राज्य विधानसभा में बताया कि बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए यह अतिरिक्त धनराशि जारी किया गया है। उन्होंने प्रश्नकल के दौरान बताया कि चराईदेव जिले के लिए 4 करोड़ रुपये और शिवसागर जिले के लिए भी 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है। इसके साथ ही जोरहाट जिले के लिए भी 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा आवंटित यह अतिरिक्त धनराशि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्य और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में उपयोग की जाएगी।

एनएससीएन (आईएम) के एक नये गुट ने की अंतरिम सरकार की घोषणा

कोहिमा, 24 जुलाई (भा)। एनएससीएन (आईएम) से अलग हुए नेताओं के एक समूह ने अंतरिम सरकार बनाने का एलान किया है। उनका दावा है कि लगभग तीन दशक पहले केंद्र सरकार के साथ हुए युद्धविराम समझौते की भावना अब खत्म हो चुकी है। नये ईस्टर्न फ्रंट के गुट ने एनएससीएन (आईएम) के दिवंगत सह-संस्थापक इसाक चिशो स्वी के बेटे इकाटो आई चिशो स्वी को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष और एचएस रामसन को उपाध्यक्ष घोषित किया। कई अन्य लोगों की अंतरिम सरकार का सदस्य और सलाहकार बनाया गया। इकाटो आई चिशो स्वी और रामसन, दोनों ही उन नेताओं में शामिल थे, जिन्हें हाल ही में एनएससीएन (आईएम) से निकाल दिया गया था। इकाटो आई चिशो स्वी के अंतरिम सरकार

शेष पृष्ठ आठ पर मिजोरम : 6.89 करोड़ से अधिक के ड्रस जब्त, दो गिरफ्तार

एजल, 24 जुलाई (भा)। मिजोरम में मादक पदार्थ रोधी तीन अलग-अलग अभियानों में 6.89 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जन्त किया गये। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इन बरामदगीयों के सिलसिले में असम के एक व्यक्ति सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बरामदगी 21 जुलाई की तड़के हुई, जब भारत-म्यांमार सीमा के निकट चंपाई जिले के सुअलरावत के पास जोखावथार-मेलबुक मार्ग पर स्कूटर सवार दो लोगों को रोका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस गश्ती दल को देखकर दोनों संदिग्ध स्कूटर छोड़कर फरार हो गये। उन्होंने बताया कि स्कूटर की तलाशी लेने पर 6.73 किलोग्राम मेथामफेटामीन



गुफ्त-गू



500% ज्यादा बारिश की वजह से ऊपरी असम में आयी बाढ़ : हिमंत



दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा, वहीं दूसरी तस्वीर में शिवसागर के एक कैंप में अपने किताबों को सुखाते हुए छात्र।

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने आज ऊपरी असम में आयी भयानक बाढ़ के लिए नगालैंड और असम के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश को जिम्मेदार ठहराया और बादल फटने या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने की किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। आज मुख्यमंत्री शर्मा ने बाढ़ से निपटने के उपायों को लेकर सभी जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद लोक सेवा भवन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच नगालैंड के मोकोकचुंग, वोखा और मोन जिलों में बारिश बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच गयी, साथ ही असम के चराईदेव

में भी बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गयी। इस दौरान नगालैंड में सामान्य से 181 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अकेले मोकोकचुंग में सामान्य से 493 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई, वोखा में सामान्य से 108 प्रतिशत ज्यादा, जबकि सोमवार को सामान्य से 45 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। उन्होंने कहा कि असम के चराईदेव जिले में एक ही समय में सामान्य से 436 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई, जबकि पड़ोसी शिवसागर में सामान्य से 134 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। शर्मा ने कहा कि आमतौर पर इस समय चराईदेव में लगभग 31.7 बारिश होती है, लेकिन यहां लगभग 170 बारिश हुई। इसी तरह शिवसागर में सामान्य बारिश लगभग 39.9 होती है, लेकिन यहां 93.2 बारिश हुई। उनके अनुसार इतनी ज्यादा बारिश ने एक ऐसी अमोखी

जोराबाट में बिना रोक-टोक के पहाड़ी कटाई से गुवाहाटी हो सकता है अनमैनेजेबल

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। राज्य सरकार ने आज चेतावनी दी कि जोराबाट के आसपास बिना रोक-टोक के डेवलपमेंट और पहाड़ी कटाई से गुवाहाटी को गंभीर खतरा है। सरकार ने कहा कि पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी लैंडस्लाइड और शहरी बाढ़ को बढ़ा रहा है और इससे शहर अनमैनेजेबल हो सकता है। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद दिसपुर में लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने है और कोर्ट द्वारा बनायी गयी एम्पावर्ड कमेटी की जांच के आधार पर इस पर बहस की जाएगी। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनायी गयी एम्पावर्ड कमेटी ने इस मामले की जांच की है और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि जोराबाट में डेवलपमेंट, खासकर यूएसटीएम और आसपास के इलाकों में गुवाहाटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उन्होंने कहा कि कमिटी इस नतीजे पर पहुंची है कि गुवाहाटी में जो बाढ़ और पानी जमा हुआ है, उसका बॉर्डर के मेधालय साइड पर हो रहे डेवलपमेंट से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि आज गुवाहाटी जो कुछ भी झेल रहा है, वह जोराबाट और उसके आसपास हो

शेष पृष्ठ आठ पर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

एनटीए ने किया 47 अधिकारियों को बर्खास्त

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को आज मंजूरी दे दी। इसमें 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देने का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गयी। सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)



विधेयक, 2024 में संशोधन किया जायेगा। इसमें प्रश्नपत्र लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच साल की जेल की सजा और/या जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों के अनुसार इसमें संगठित तरीके से किये गये प्रश्नपत्र लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल की सजा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा कानून के अंतर्गत पांच साल की जेल की सजा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा कानून के अंतर्गत पांच साल तक की जेल का प्रावधान है, जबकि संगठित रूप से धोखाधड़ी और प्रश्नपत्र

लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए पांच से 10 साल तक की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य उन संगठित गिरोहों और संस्थानों को गलत कृत्य करने से रोकना है, जो आर्थिक लाभ के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके प्रावधानों से संरक्षण प्रदान करना है। मौजूदा कानून का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी आदि जैसी भर्ती परीक्षाओं और नीट, जेईई तथा सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, कदाचार और

शेष पृष्ठ आठ पर

नीट प्रश्नपत्र लीक को रोकने संबंधी कदमों की करेंगे कड़ी निगरानी : एससी

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों की कड़ी निगरानी करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्षों से चली आ रही तथ्य व्यवस्थाओं ने परेशानी खड़ी की है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) की अजी समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अग्रवे की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष

शेष पृष्ठ आठ पर

हिमाचल : वाहन पर चढ़ानें गिरने से 13 लोगों की मौत

शिमला, 24 जुलाई (भा)। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में उदयपुर-पांगी मार्ग पर पहाड़ी से विशाल चट्टानें एक टेक्सी पर गिरने से आज छह महीने के एक शिशु समेत 13 लोगों की मौत हो गयी, जबकि दो अन्य लोग बाल-बाल बच गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कुल्लू से किलाड़ जा रहे वाहन में 15 लोग सवार थे। इसने बताया कि कटू नाला के निकट विशाल चट्टानें गिरने से वाहन पूरी तरह उसके नीचे दब गया और वाहन के पिछले हिस्से में आग लग गयी। मौके पर मौजूद राहगीरों और सेना के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें वाहन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त और आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। घटना की पुष्टि करते हुए भ्रमरों के विधायक जनक राज ने कहा कि वाहन में सवार 15 लोगों में से 13 की मौत हो गयी, जबकि वाहन से बाहर कूदे दो लोग बच गये। उन्होंने

शेष पृष्ठ आठ पर

अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने व कानूनों का उल्लंघन करने पर 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म किये गये बंद

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। सरकार ने आज संसद में कहा कि अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने पर पिछले दो वर्ष में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि उसने सोशल मीडिया मंचों पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापनों की हालिया खबरों को गंभीरता से लिया है और उन्हें तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए नोटिस जारी किये गये हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग



(एनसीपीसीआर) ने भी इन सोशल मीडिया मंचों को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले दो वर्ष में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारत में सार्वजनिक पहुंच हेतु 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दिया गया है। वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे

शेष पृष्ठ आठ पर

80 हजार प्रभावितों तक राहत पहुंचाना अब भी चुनौती

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज कहा कि राज्य सरकार अभी तक बाढ़ प्रभावित कम से कम 80,000 लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचा सकी है, क्योंकि सभी इलाकों तक पहुंचने का कोई प्रभावी रास्ता प्रशासन को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने यहां आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि राज्य में करीब 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गयी है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 40,000 घर अब भी बिजली से वंचित हैं। शर्मा ने कहा कि हम सभी लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग छूट गये हैं। नजीरा विधानसभा क्षेत्र में, 30 प्रतिशत इलाके या लगभग 50,000 लोगों तक नहीं पहुंचा जा सका है। शिवसागर में, 20 प्रतिशत इलाके या 30,000 लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह संख्या 10,000 कम या ज्यादा हो सकती है (उन 80,000 प्रभावित लोगों में से जिन तक अभी पहुंचना बाकी है)। उन्होंने कहा कि हालांकि ज्यादातर जगहों पर पानी कम होने लगा है, लेकिन सड़कों पर गाद और कीचड़ की मोटी परत जम जाने के कारण कई स्थानों पर लोगों का संपर्क लगभग पूरी तरह कट गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चराईदेव जिले में आज तक सभी इलाकों में राहत सामग्री भेज दी गयी है। शर्मा ने कहा कि बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है और ऊपरी असम के सबसे अधिक प्रभावित तीन जिलों में कई मंत्रियों को राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने हवाई मार्ग से राहत सामग्री गिराने की भी कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में राहत सामग्री क्षतिग्रस्त हो गयी। आज हम भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि यह तय किया जा सके कि राहत सामग्री की पैकेजिंग किस तरह की जाए, जिससे गिराने के दौरान उसे नुकसान न पहुंचे। शर्मा ने कहा कि हालांकि कुछ इलाके अब भी प्रशासन की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन हम प्रभावित क्षेत्र तक राहत पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि असम के अन्य जिलों से अतिरिक्त नौकाएं, राहत सामग्री और आवश्यक वस्तुएं भेजी जा रही हैं, जिससे शेष कटे हुए इलाकों तक भी जल्द से जल्द सहायता पहुंचा दी जाएगी। असम में आज भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। अब तक बाढ़ से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि

शेष पृष्ठ आठ पर

विपक्ष प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा, मानसून सत्र का पहला सप्ताह चढ़ा हंगामे की भेंट



नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध कायम रहा और

लोकसभा एक बार के स्थगन, वहीं राज्यसभा दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका तथा प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सके। लोकसभा की बैठक सुबह शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिर्ला ने 26 जुलाई को मनाने जाने वाले कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। इसके बाद सदन ने कारगिल संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को मौन रखकर

शेष पृष्ठ आठ पर

॥ श्री हरि ॥

शोक-संदेश

जन्म :
10.06.1965

स्वर्गारोहण :
22.07.2026

स्व. सुरेंद्र कुमार सेठिया (नेत्रदानी)

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय सुरेंद्र कुमार सेठिया (सुपुत्र स्व. अजय सिंह जी सेठिया, गंगाशहर निवासी) का स्वर्गवास दिनांक 22.07.2026 बुधवार को दिल्ली में हो गया है।

** शोकाकुल **

रणजीत	- प्रेमलता सेठिया	(अग्रज)	- अग्रजवधु)
नरेंद्र	- संगीता सेठिया	(अनुज)	- अनुजवधु)
प्रेम	- किशोर जी बंद	(बहन)	- बहनोई)
स्वीटी	- सुमित जी अग्रवाल	(भतीजी)	- भतीजी दामाद)
पूजा	- अंकित जी छाजेड़	(पुत्री)	- पुत्री दामाद)
विनय	- रीता सेठिया	(भतीजा)	- भतीजावधु)
तन्मय	- ज्योति सेठिया	(भतीजा)	- भतीजावधु)
संदीप	- अरुणा सेठिया	(पुत्र)	- पुत्रवधु)
नवीन	- प्रज्ञा सेठिया	(भतीजा)	- भतीजावधु)
अभिषेक	- ज्योति सेठिया	(भतीजा)	- भतीजावधु)

पलक पाश्ची, आराध्या, मेहान, अमायरा शानवी, इवाना, प्रीभीका एवं एकांश (पौत्र-पौत्री) दिवित, सनय एवं धारवी (द्रोहिता-द्रोहिती) प्रतिष्ठान एवं निवास स्थान मेसर्स अजय सिंह सुरेंद्र कुमार बिलासीपाड़ा (असम)

-: निवास स्थान :-

A.S Group Associates Bilasipara, Delhi

बैठक

दिनांक 27.07.2026 (सोमवार) को अपराह्न 3 बजे से सायं 6 बजे तक, बिलासीपाड़ा निवास स्थान पर

संपर्क सूत्र - 94351-25533, 70025-93092

पेज : 9 खाटू श्याम जी, पुष्कर और रामदेवरा का बदलेगा स्वरूप

पेज : 8 झारखंड में गोलीबारी : अपराधियों के गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि खोजना बड़ी चुनौती : महंत

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत ने आज विधानसभा में दी। बाढ़ और कटाव से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर लाये गये एक निजी संकल्प प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हालांकि राज्य में भूमिहीन नागरिकों के पुनर्वास के लिए कानूनी प्रावधान और भूमि आवंटन नीतियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन उपयुक्त सरकारी भूमि की उपलब्धता एक बड़ी बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 जैसे कानून और विभिन्न सरकारों द्वारा बनायी गयी भूमि आवंटन नीतियां भूमिहीन लोगों के पुनर्वास के प्रावधान करती हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि असम भूमि नीति 2019 प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हुए परिवारों को प्राथमिकता देती है। महंत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए मौजूदा भूमि नीति में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने ध्यान दिलाया कि उपलब्ध सरकारी भूमि के एक बड़े हिस्से पर पहले से ही अतिक्रमण हो चुका है, जिसमें स्वयं भूमिहीन

परिवार भी शामिल हैं, जिससे नये सिरे से भूमि का आवंटन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चर क्षेत्रों का चल रहा सर्वेक्षण सरकारी भूमि की पहचान करने में मदद करेगा, जिसे आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पुनर्वास के लिए आवंटित किया जा सकता है। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद ने इस समस्या से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपायों का आह्वान किया। वहीं जाकिर हुसैन सिकंदर ने कहा कि जब कटाव से विस्थापित परिवार राज्य के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो कई बार उनके साथ बाहरी जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने सरकार से ऐसे परिवारों को कटाव-प्रभावित प्रमाण पत्र जारी करने और उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके अलावा रायजोर दल के विधायक महबूब मुकार ने कटाव प्रभावित परिवारों द्वारा झेली जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों को रेखांकित किया और आरोप लगाया कि विस्थापन के बाद कई परिवारों को सामाजिक और प्रशासनिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एआईयूडीएफ विधायक मुजीबुर रहमान और टीएमसी विधायक शेरमान अली अहमद ने भी भूमिहीन लोगों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और पुनर्वास मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की।

गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की मांग

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुबैर अनम मजुमदार ने एक निजी संकल्प के माध्यम से गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से उनके लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित पहचान और पेरोवर सुरक्षा नहीं मिलती है। मजुमदार ने ऐप-आधारित परिवहन, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स डिलीवरी,

लॉजिस्टिक्स, होम सर्विसेज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों को इसमें शामिल करने पर जोर दिया। मजुमदार ने गिग वर्कर्स की स्थिति पर दुख जताते हुए कहा कि वे कोई अदृश्य ताकत नहीं बल्कि जीते-जागते ईंसान हैं, लेकिन उन्हें वह सम्मान और मान्यता नहीं दी जाती जिसके वे हकदार हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई अपार्टमेंट ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को लिफ्ट का उपयोग तक नहीं करने देते, जबकि पालतू कुत्तों को इसकी अनुमति होती है। उन्होंने अफसोस जताया कि देश में काम की

गरिमा को अभी तक उचित पहचान नहीं मिली है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अक्सर उसकी आर्थिक स्थिति से तोला जाता है। उन्होंने बस बात पर जोर दिया कि गिग वर्कर्स के पास न तो कोई सामाजिक सुरक्षा है और न ही अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कोई व्यवस्था। मजुमदार ने कहा कि हालांकि समाज की मानसिकता बदलने में समय लगेगा, लेकिन गिग वर्कर्स को एक गरिमापूर्ण जीवन और सम्मान दिलाने का सबसे त्वरित और प्रभावी तरीका उनके अधिकारों के लिए कड़ा कानून बनाना है।

शीघ्र भरे जाएंगे गांव प्रधानों के 2,499 खाली पद

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत ने बताया कि वर्तमान में सरकार के अधीन कुल 11,859 राजस्व गांवों में गांव प्रधान नियुक्त हैं, जबकि राज्य भर में अब तक 2,499 गांव प्रधानों के पद खाली पड़े हुए हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं और नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भाजपा विधायक विनोद हजारिका के पूछे गये एक मौखिक सवाल के जवाब में उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा राज्य में गांव प्रधानों का बढ़ा हुआ मानदेय एक अक्तूबर 2025 से लागू कर दिया है, जिसके तहत उन्हें अब हर महीने 14,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि गांव प्रधानों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी वर्तमान में सरकार के विचारधीन है।

वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला विधेयक रास में पेश

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। राज्यसभा में सरकार ने आज एक विधेयक पेश किया, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। सदन ने इस विधेयक के विरोध में विपक्ष द्वारा लाये गये प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। नोट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटान ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिये संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की संस्था पर आधारित है किंतु यह संविधान के उन संदर्भों की अगन्तेश्वरी नहीं है, जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। ब्रिटान ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार तीन वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एकसमान दर्जा नहीं दिया था।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा, भोजन व आवश्यक सहायता बढ़ाने की मांग, अजमल ने सीएम को सौंपा ज्ञापन

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। एआईयूडीएफ सुग्रीमो एवं बिनाकांदी के विधायक बदरुद्दीन अजमल ने आज राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने असम के मौजूदा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं, आवश्यक सेवाओं, शिशु आहार तथा पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव और बिनाकांदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि बाढ़ ने गंभीर मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय तबाही मचाई है, जिससे हजारों परिवार बेघर होकर अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा विशाल कृषि भूमि के जलमग्न होने से

खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और सड़कों तथा रेल नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचने से कई दूर-दराज के गाँव संपर्क से कट गए हैं। अजमल ने दूषित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को तत्काल चिकित्सा तथा पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे संबंधित सभी विभागों को राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के निर्देश दें। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित सभी गाँवों और राहत शिविरों में पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मोबाइल रेडिक्रल टीम, एम्बुलेंस और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

तुरंत सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल, शिशु आहार, मच्छर नियंत्रण, स्वच्छता सामग्री और पशु चारे की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एआईयूडीएफ अध्यक्ष ने सरकार द्वारा अब तक उठाए गए सक्रिय कदमों तथा जिला प्रशासन और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना भी की। हालांकि, उन्होंने आग्रह किया कि मौजूदा राहत अभियानों को और अधिक मजबूत तथा तेज किया जाए ताकि कोई भी प्रभावित व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आश्रय, पेयजल और स्वच्छता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में असम की मुलाकात की। राष्ट्रपति सुमू ने भारत-रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी संवाद किया।

पीआईबी गुवाहाटी की वार्ता मीडिया कार्यशाला आयोजित



हुए उन्होंने कहा कि जनगणना के अंतिम लाभार्थी आम जनता ही हैं, क्योंकि यही आंकड़े कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण का मार्गदर्शन करते हैं। सुश्री चंदा ने जनगणना के दो चरणों, इसमें डिजिटल तकनीक के उपयोग, स्व-गणना की सुविधा, एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और प्रमाणकों व पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला। जनगणना की तैयारियों पर बात करते हुए जिला आयुक्त किमनेई

आजीविका के क्षेत्रों में बक्सा द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने जिले की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि बक्सा को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित जेआरडी टाटा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, जिले ने सालबारी में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की मेजबानी की है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पहल के तहत 20 मॉड्रिक टन शहद का संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया है। इससे पूर्व, पीआईबी गुवाहाटी की संयुक्त निदेशक पावनी गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की प्रामाणिक व समयबद्ध जानकारी प्रसारित करने में वार्ता कार्यशाला के महत्व को रेखांकित किया। आगामी जनगणना के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जनता में जागरूकता फैलाने, प्रतियोगी को दूर करने और नागरिकों को सहो जानकारी देकर जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने में मीडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

3.12 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत के अनुसार असम के 27 जिलों के कुल क्षेत्रफल 3,35,16,927 बीघा, 1 कठा और 8 लेचा है। इसमें से 3,33,681 बीघा, 0 कठा और 8 लेचा भूमि पीजीआर के रूप में 5,90,124 बीघा, 1 कठा और 14 लेचा भूमि वीजीआर के रूप में और 8,83,911 बीघा, 0 कठा और 2 लेचा भूमि जलाशयों के अंतर्गत आती है। विपक्ष के नेता वाजिद अली चौधरी के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने आगे बताया कि राज्य में कुल 18,01,953.536 हेक्टेयर वन भूमि मौजूद है। असम की कुल भूमि में से 16,144.0117 हेक्टेयर

(1,20,675 बीघा, 1 कठा, 17 लेचा) पर अरुणाचल प्रदेश, 3,441.8601 हेक्टेयर (25,727 बीघा, 3 कठा, 7 लेचा) पर मेघालय, 3,675.78 हेक्टेयर (27,476 बीघा, 1 कठा, 0 लेचा) पर मिजोरम और 59,490.21 हेक्टेयर (4,44,685 बीघा, 1 कठा, 0 लेचा) पर नगालैंड राज्य का अवैध कब्जा है। वर्तमान में असम की 3,12,982.175 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। वर्तमान में 1,38,678 बीघा, 1 कठा और 19 लेचा पीजीआर भूमि, 2,98,708 बीघा, 2 कठा और 10 लेचा वीजीआर भूमि तथा 71,660 बीघा, 0 कठा और 15 लेचा जलाशय भूमि पर भी अतिक्रमण दर्ज किया गया है।

असम में जन्म 19.6 और मृत्यु दर 6.1 दर्ज

जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 6,17,367 तक पहुंच गया। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2024-25 में जीवित जन्मों की संख्या घटकर 5,27,591 और वर्ष 2025-26 में 5,18,260 रह गयी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून महीने तक राज्य में कुल 1,01,942 जीवित बच्चों का जन्म दर्ज किया गया है, जिनमें 52,552 लड़कियां और 49,390 लड़के शामिल हैं। दूसरी ओर नमूना पंजीकरण प्रणाली के तहत वर्ष 2011 से जून 2026 तक के आंकड़ों पर नज़र

एनएचएम में हैं 18,681 संविदा कर्मचारी

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने विधानसभा में बताया कि वर्तमान में असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कुल 18,681 कर्मचारी और अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एआईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान के पूछे गये एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी कर्मचारी अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये हैं। ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि वे योग्यता के अनुसार स्थायी पदों के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।

एक संशोधित विधेयक पेश

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। असम विधानसभा के बजट सत्र के आज 11वें दिन सदन के पटल पर एक संशोधित विधेयक पेश किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. रंजीत पेगु ने माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2026 को सदन के पटल पर रखा।

तेममं की हुई साधारण सभा



गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। अखिल भारतीय तैराथ महिला मंडल के निदेशन में तैराथ महिला मंडल गुवाहाटी द्वारा सत्र 2025-27 की प्रथम वार्षिक साधारण सभा आज अध्यक्ष सुशीला मालू की अध्यक्षता में स्थानीय तैराथ धर्मस्थल में आयोजित हुई। युगप्रधान आचार्य महाश्रमण के विद्वान सुश्रिय मुनि आनंद कुमार कालू टाणा -2 ने महिलाओं के व्यक्तित्व में मेहनत, हिम्मत और लज्जा इन तीनों गुणों का समावेश करके मंडल व संघ की प्रभावना में अपने श्रम व शक्ति को निहित करने का आह्वान किया। मुनिप्रवच के मुखारविंद से मंगल पाठ सुनकर बहनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। नमोकार महामंत्र की मधुर ध्वनि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। मंडल की बहनों द्वारा मंगलाचरण के रूप में प्रेरणा गीत तथा मधुर संगान किया गया। अध्यक्ष सुशीला मालू ने उपस्थित बहनों का स्वागत और मंडल के हर कार्य में सभी बहनों की सक्रिय सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा मुनिश्री के सेवा दर्शन का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया। तैराथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कार्यकारीणी सदस्य मधु डागा ने संविधान का वाचन किया।

गत बैठक के प्रतिवेदन एवं कन्या मंडल प्रतिवेदन का वाचन किया गया एवं उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। मंत्री सुचित्रा छाजेड़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर में आयोजित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सेवा गतिविधियों का विस्तृत विवरण रखा एवं उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। कोषाध्यक्ष विनीता सुराणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। तत्पश्चात कन्या मंडल की कन्याएं दिशा सुराणा, महंक बैद एवं सिमरन भादानी ने मर्यादा हमारी पहचान बने विषय पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे संस्कार निर्माण शिविर के ईस्ट जोन संस्कार एवं प्रेक्षाध्यान के प्रशिक्षक रवि छाजेड़ ने स्वांस किया या विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार संपत मिश्रा, विवेक सांगानेरिया, गोपाल मिश्रा एवं कन्हैया झा का फूलाम गमोड़ा आदि से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री सुचित्रा छाजेड़ ने किया। आभार ज्ञापन सहमंत्री (प्रथम) संध्या कोटारी ने किया। इस आशंका की जानकारी प्रचार प्रसार मंत्री सुनीता मालू ने दी।

स्वत्वाधिकारी प्रातः खबर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, खबर बिल्डिंग, दूसरा तल्ला, साईफिल्ड फेक्ट्री, कालापहाड़, गुवाहाटी- 781016 के लिए **श्याम सुंदर लाटा** द्वारा प्रकाशित तथा उनके लिए पीजी इंडिया लिमिटेड, मिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कालापहाड़, गुवाहाटी-16 (असम) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

E-mail : pratabkhobar5@gmail.com, pratath_khabar@yahoo.com, **दूरभाष/फैक्स :** 0361-2492131, **मो.** : 091270-70355, **जोरहाट कार्यालय :** 0376-2370042, **फैक्स :** 0376-2370043, **E-mail :** pkhbarjrt@gmail.com

***प्रकाशन से उत्पन्न सभी विवाद गुवाहाटी न्यायालय के अधीन।**

एडिटर इन चीफ : चंद्रप्रकाश शर्मा

संपादक : परमेश्वर सिंह

अब नये व आकर्षक पैक में

चौधरी

Sattu

*Nourishing & Delicious
Instant Food*

पारंपरिक स्वाद व सुगंध से भरपूर

चुने हुए उत्कृष्ट
चने से बना

पोषण से भरपूर
चौधरी सतू खाएं
स्वस्थ रहें

Our other products Special Quality
TRISHUL BRAND BESAN
&
ROASTED CHANA

A quality product from
SHIV SHAKTI ENTERPRISE
R.B. Lane, Jorhat (ASSAM)
Customer Care E-mail : shivshaktijrt@gmail.com
Contact. : 0376-2300030, 94350-92761

नगांव में 40 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में, कलंग नदी का बढ़ा जलस्तर

नगांव, 24 जुलाई (ख.सं)। कार्बी आंलांग की पहाड़ियों से उतरकर आये तेज बहाव के पानी ने नगांव जिले के विस्तृत क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया है। कलियाबर और सामागुड़ी राजस्व चक्र के कई गांवों में पहले से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। अब निशारी और हारिया नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कामपुर राजस्व चक्र के 18 तथा नगांव सदर राजस्व चक्र के 7 गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार कामपुर राजस्व चक्र के तेतेलीसरा ग्रांट, महाद, पूर्व कावेमारी, पश्चिम नामबर लालुंगा गांव, पश्चिम कठियातली, सरपथार, मिकिरगांव, गरुबंधा गांव, तेतेलीसरा गांव, पूर्व खालैभंगा, पश्चिम कावेमारी, पश्चिम खालैभंगा, बामुनीजान, दरंगीगांव, कछारीखंडा, केकुरीबाड़ी, भलुकागुड़ी और कलाइखोवा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।इसी प्रकार, नगांव सदर राजस्व चक्र के गड़ेहांगी, दक्षिण



गमारीआटी, बरकंदली मिकिरगांव, उरिया ग्रांट रंगलु, मिकिरपुर उरिया, कचुपीट तथा चकरी गांव भी जलमग्न हैं।वहीं सामगुड़ी राजस्व चक्र के

सोनारीबाली, मिसागांव, खलिहामारी शियालेखाटी, पामागांव, आमणिगांव, सामगुड़ी ग्रांट, नंबर-2 गरुमरा, बरदल, कठालगुरी,

भोमोरगुरी, नंबर-2 भरागुरी तथा पदुमणि गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं।जिले के इन तीनों राजस्व चक्रों में लगभग 3,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। साथ ही 2,280 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। पिछले चार दिनों से बाढ़ की चपेट में रहे कलियाबोर राजस्व चक्र की स्थिति में अब सुधार देखा जा रहा है। बाढ़ से लगभग 4,000 से अधिक पशुधन भी प्रभावित हुए हैं। नगांव जिला प्रशासन युद्धस्तर पर राहत एवं सहायता कार्य जारी रखे हुए है।उधर जिले के शिलघाट में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे बर रहा है। कामपुर में कपिली नदी भी खतरे के निशान से नीचे है। नगांव शहर में कलंग नदी का जलस्तर बढ़ा है हालांकि यह अभी भी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर नीचे बरह रही है। वहीं, राहा में कलंग नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है।

पूप्रमायुमं के निर्वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान का अभिनंदन

सिलचर, 24 जुलाई (ख.सं)। पूर्वोत्तर प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के निर्वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष श्री पंकज जालान के दो दिवसीय निजी प्रवास के दौरान बैद्यनाथ धाम, देवघर आगमन पर मारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा द्वारा उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। देवघर शाखा के कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष साकेत छावछरिया, सदस्य केशव चोखानी एवं सर्वेश मोदी ने जालान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा उनके सामाजिक एवं संगठनात्मक योगदान की सराहना की। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष साकेत छावछरिया ने जानकारी दी कि मारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा इस वर्ष अपना 36वां श्रावण कांवड़िया सेवा शिविर आयोजित करने जा रही है। इस सेवा शिविर में प्रतिवर्ष लाखों कांवड़िया श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें शाखा



द्वारा पूर्णतः निःशुल्क भोजन, विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस विशाल सेवा अभियान में हजारों स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार से अपना योगदान देते हैं। कोई आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है, तो कोई अपना

बहुमूल्य समय देकर श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहता है। कार्यक्रम के दौरान देवघर शाखा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पूर्वोत्तर प्रदेश के सभी समाजबंधुओं एवं श्रद्धालुओं को इस ऐतिहासिक सेवा शिविर में पधारकर सेवा एवं सहयोग का सहभागी बनने का प्रेरणामूर्ति मित्रज भी दिया।

पूर्वोत्तर में भाषाई एकात्म के सूत्र की पड़ताल करना आज की जरूरत : प्रो. विनोद कुमार मिश्र

सिलचर, 24 जुलाई (ख.सं)। शिक्षा संस्कृति उ्थान न्यास, नयी दिल्ली के भारतीय भाषा मंच, पूर्वोत्तर द्वारा कल मणिपुर विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा मंच, मणिपुर इकाई स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अध्यक्ष के रूप में प्रो एस इमोबा सिंह, पूर्व मानविकी संकाय प्रमुख एवं भारतीय भाषा समिति, मणिपुर विश्वविद्यालय के समन्वय अधिकारी की उपस्थिति रही।मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय भाषा मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक एवं हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय के आचार्य विनोद कुमार मिश्र मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न अतिथि की भूमिका में ब्रह्मचारीमयुम बिल्की शर्मा, जिला कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इम्फाल, शिक्षा संस्कृति उ्थान न्यास,उत्तर-पूर्व के प्रचार प्रसार संयोजक एवं मेघालय प्रान्त संयोजक डॉ. आलोक सिंह उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय मंगलाचरण से हुई। इसके बाद इस कार्यक्रम की संयोजक तथा मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की आचार्य कंचन शर्मा ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो एस इमोबा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यदि आप अपनी भाषा से प्यार करते हैं तो आप अपने समाज और लोगों से प्यार करते हैं। इसके साथ उन्होंने मातृभाषाओं में उपलब्ध साहित्य को बचाएं रखने का आवाहन किया।इसके बाद प्रो विनोद कुमार मिश्र ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत की प्रत्येक मातृभाषा में निहित भारतीयता की तलाश करना ही हमारा उद्देश्य है। पूर्वोत्तर में भाषाई एकात्म के सूत्र की पड़ताल करना आज की जरूरत है। भारतीय भाषा मंच ने भारत की सभी भाषाओं की ताकत को तलाशने की लगातार कोशिश की है। आभासी माध्यम से जुड़े भारतीय भाषा

मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. राजेश्वर कुमार ने कहा कि भाषाओं का विभाजन यह भाषाओं के लिए ठीक नहीं बल्कि उनका भारतीयकरण होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भाषा मंच भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए कार्य करती है सभी भाषाओं को महत्व देती है। तत्पश्चात ब्रह्मचारीमयुम बिल्की शर्मा ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा के प्रति रुचि को विकसित करना चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा में ही हमारी संस्कृति, कला दर्शन प्रमुखता पाते हैं। इसके उपरांत डॉ. आलोक सिंह ने पूर्वोत्तर में भारतीय भाषा मंच के कार्यों का उद्घेख किया। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो अखिलेश शंखधर, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आरके भुवनसाना सिंह, वानिकी संकाय के सहायक आचार्य डॉ विवेक वैष्णव आदि भाषाविद,विद्वार्थी, शोधार्थी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक बंदी

नगांव, 24 जुलाई (ख.सं)। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में बजाली जिले के पाटशाला के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान निपुण तालुकदार के रूप में हुई है। आरोप के अनुसार करीब दो दिन पहले युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक खबर सोशल मीडिया पर साझा कर उस पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की तस्वीर साझा कर भी कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ पोस्ट किये, जिनमें असम को नेपाल और श्रीलंका जैसी अस्थिर परिस्थितियों की ओर ले जाने जैसी टिप्पणियां की गयी थीं। स्थानीय लोगों के आरोप के अनुसार निपुण तालुकदार पहले भी सोशल मीडिया पर आम लोगों को निशाना बनाकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और उपहास करता रहा है।

असम बुक ऑफ रिकार्ड्स में हितार्थ चाचान ने दर्ज कराया नाम



तेजपुर, 24 जुलाई (ख.सं)। असम बुक ऑफ रिकार्ड्स ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे कम आयु के भक्ति श्लोक रत्न के रूप में रतन कुमार एवं श्यामा चाचान के पौत्र तथा लोकेश कुमार चाचान एवं नैसी किह्ला के सुपुत्र हितार्थ चाचान को शामिल किया है। गुवाहटी के कंगारू

किड्स के एल्केजी के छात्र हितार्थ चाचान ने श्रीमद् भागवद गीता के अध्याय -2,श्लोक -47 का नमस्कार मुद्रा के साथ मधुर स्वर, स्पष्ट उच्चारण, शुद्धता एवं उत्कृष्ट लय का परिचय देते हुए मात्र 12 सेकंड में पाठ कर अपना दूसरा रिकार्ड स्थापित किया।

हाजो के बरम्बई पहाड़ में भयावह भूस्खलन

हाजो, 24 जुलाई (ख.सं)। हाजो स्थित बरम्बई पहाड़ में मूसलाधार बारिश के कारण भीषण भूस्खलन हुआ । भूस्खलन के कारण बरम्बई आंचलिक श्रीश्री दुर्गा मंदिर के सभागार की दीवार ढह गयी। पहाड़ से मलबा गिरने के कारण मंदिर की कई वस्तुएं नष्ट हो गयीं और करीब लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान होने की जानकारी सामने आयी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मंदिर के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घटनास्थल पर प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोग स्थिति को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं।

कोकराझाड़ कैन्सर सेंटर को मिली मान्यता



कोकराझाड़, 24 जुलाई (ख.सं)। असम कैन्सर केयर फाउंडेशन की इकाई कोकराझाड़ कैन्सर सेंटर को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता अस्पताल द्वारा

विश्वस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण कैन्सर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इसे संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। भविष्य में भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।



सिलचर, 24 जुलाई (ख.सं)। असम विश्वविद्यालय, सिलचर के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्लब द्वारा विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में हिमालय की भूमिका विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। यह संगोष्ठी 24 और 25 जुलाई 2026 तक

तेजपुर में श्री मारवाड़ी दुर्गा पूजा समिति की हुई बैठक



तेजपुर, 24 जुलाई (ख.सं)। श्री मारवाड़ी दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक श्री मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला प्रांगण में आयोजित की गयी। समिति के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा की अनुपस्थिति मे वरिष्ठ उपध्यक्ष दीनदयाल आसोपा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक मे प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाने के

लिए कई विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक मे सचिव जीतू बोरड़, पूर्व अध्यक्ष प्रेम झंवर, पूर्व सचिव बिष्णु डागा, पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण बाहेती, सलाहकार रामरतन पांड्या, के अलावा राजशर्मा, आनंद शर्मा, जुगल पांड्या, प्रमोद बगड़ा, जीतेंद्र लढा, कामछया पारीक, राजेश अग्रवाल आदि शामिल थे।

बजे शुरू हुई इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा और हर कोई भक्ति रस में सराबोर नजर आया। इस दौरान भक्तों में रथ की पवित्र रस्सी को खींचने के लिए होड़ मची रही। लोगों की अटूट मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर

भीषण गर्मी के बीच यात्रा मार्ग पर जगह-जगह भक्तों के लिए शीतल जल, शरबत और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गयी थी, जिसकी सभी ने भूरि-भरि प्रशंसा की। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम रथ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी,

ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की एक झलक पा सकें और उत्सव हर्षोहास के साथ संपन्न हो सकें। **सिलचर से हमारे संवाददाता के अनुसार** भक्तिमय वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज द्वारा आज सिलचर में उल्टा रथ यात्रा या बहुदा यात्रा का आयोजन किया गया।

लमडिंग में भूमि हस्तांतरण को लेकर उठे सवाल, पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच की मांग तेज

लमडिंग, 24 जुलाई (ख.सं)। होजाई जिले के लंका राजस्व चक्र अंतर्गत लमडिंग मौजा स्थित एक भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अध्ययन के बाद स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल उठे हैं। इन अभिलेखों के अनुसार जिस भूमि का नामांतरण पहले रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में दर्ज था, बाद के वर्षों में वही भूमि दो निजी व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दिखाई देती है। इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अब तक किसी उपक्षम न्यायालय, जांच एजेंसी अथवा सरकारी विभाग ने इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध कार्य की पुष्टि नहीं की है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार लंका राजस्व चक्र के अंतर्गत जोंगदिशा गांव

स्थित लगभग 1 बीघा 4 कठ। भूमि को 7 फरवरी 2012 को रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तत्कालीन भू-स्वामियों से खरीदा गया था। इसके बाद संबंधित राजस्व प्रक्रिया पूरी करते हुए म्यूटेशन केस संख्या 347/2011-12 के माध्यम से भूमि का नामांतरण कंपनी के पक्ष में दर्ज किया गया। बाद में सामने आए राजस्व अभिलेखों से पता चलता है कि वर्ष 2017 में म्यूटेशन केस संख्या 2232/2017 के तहत उस भूमि का नामांतरण दो निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ लिया और स्थानीय लोगों के बीच यह जिज्ञासा बढ़ी कि पहले से कंपनी के नाम दर्ज भूमि का बाद में नामांतरण किस प्रक्रिया के तहत किया गया तथा क्या उस समय लागू सभी नियमों और औपचारिकताओं का पालन किया गया था। भूमि कानून से जुड़े जानकारों का कहना है कि नामांतरण केवल राजस्व अभिलेखों



को अद्यतन करने की प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य भूमि कर और प्रशासनिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है। केवल नामांतरण आधार पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व अंतिम रूप से सिद्ध नहीं होता। भूमि से जुड़े अधिकारों

अथवा दस्तावेजों की वैधता का निर्णय केवल सक्षम न्यायालय या अधिकृत प्राधिकारी ही कर सकता है। रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम पहले भी राज्य में संचालित रूप से सिद्ध नहीं होता। भूमि से जुड़े अधिकारों

में रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी ऐसी कंपनी के नाम दर्ज भूमि का बाद में नामांतरण किया जाता है, तो संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न रहे। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि नामांतरण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप संपन्न हुई थी या नहीं। यदि सभी नियमों का पालन किया गया है, तो जांच से यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी और अनावश्यक विवाद समाप्त हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी भूमि के नामांतरण से पहले आवेदन, पंजीकृत विक्रय बिलेख, सत्यापन रिपोर्ट, वित्तीय गतिविधियों के कारण सार्वजनिक चर्चा

आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। इसलिए इस मामले में भी वास्तविक स्थिति का पता तभी चल सकेगा जब संबंधित मूल सरकारी फाइलों और अभिलेखों की विस्तार से जांच की जाएगी। मामले के दौरान उस समय संबंधित राजस्व कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक चर्चा में आए हैं। लेकिन यह उद्घेख करना आवश्यक है कि अब तक किसी विभागीय जांच या न्यायिक आदेश में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी या निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी अधिकारी की भूमिका पर अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के नाम बाद के नामांतरण रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनका उद्घेख केवल उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के संदर्भ में किया गया है। इस समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि को प्रभावित करना या उनके खिलाफ कोई आरोप

लगाना नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। भूमि प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि किसी राजस्व अभिलेख को लेकर सार्वजनिक स्तर पर संदेह उत्पन्न होता है, तो प्रशासन द्वारा समय पर उसकी जांच किया जाना अनिवार्य होता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होता है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू करते हैं, तो घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई थी या फिर किसी स्तर पर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है। भूमि विशेषज्ञों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड केवल प्रशासनिक दस्तावेज होते हैं।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर की अहम चर्चा

इटानगर, 24 जुलाई (एजें.)। गवर्नर केटी परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की विकास प्राथमिकताओं, अहम प्रोजेक्ट्स को लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं व मौसम से जुड़ी घटनाओं से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। कल यहां लोक भवन में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान परनाइक ने खांडू और टीम अरुणाचल प्रदेश को 10 साल की समर्पित जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के जन-केंद्रित दृष्टिकोण ने शासन को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है, खासकर दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। सेवा आपके द्वार जैसी प्रमुख



पहलों की सराहना करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस कार्यक्रम ने सरकारी सेवाओं को लोगों

के घर-घर तक पहुंचाकर जनसेवा वितरण में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलों

ने जनता का भरोसा मजबूत किया है और समावेशी विकास की भावना को बढ़ावा दिया है। गवर्नर ने ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवा वितरण को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। टेक्नोलॉजी-आधारित प्रशासन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, निगरानी करने और मूल्यांकन के लिए जियोस्पेशियल एप्लिकेशन, सैटेलाइट इमेजरी और डेटा एनालिटिक्स के अधिक उपयोग की वकालत की।

उन्होंने कहा कि ये उपकरण निर्णय लेने की क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं, आपदा की तैयारी में सुधार कर सकते हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लाभ के लिए कल्याणकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों को समय पर लागू करना सुनिश्चित कर सकते हैं।

मेघालय ने पहला स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किया लांच



सिर्फ एक रैंकिंग सिस्टम के बजाय एक डायग्नोस्टिक और प्लानिंग टूल के तौर पर काम करना है। यह फ्रेमवर्क स्कूल हेड, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों और एजुकेशन अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनल ताकत पहचानने, कमियों को दूर करने और स्कूल की

ओवरऑल तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह असेसमेंट पूरी तरह से स्कूलों द्वारा सबमिट और सर्टिफाइड ऑथेंटिकेटेड यूडीआईएसई+ डेटा पर आधारित है। स्कूलों को 17 परफॉर्मेंस ग्रेड में बांटा गया है, जो उत्कर्ष (आउटस्टैंडिंग) से लेकर आकांक्षा-10 (इंटेंसिव सपोर्ट) तक हैं, जिससे सिर्फ़ रिलेटिव रैंकिंग के बजाय तय बेंचमार्क के आधार पर इवैल्यूएशन पक्का होता है। डिपार्टमेंट ने कहा कि एमएसपीजीआई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) पर बनाया गया है, जो नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क को हर स्कूल लेवल तक बढ़ाता है।

डीजीपी की मौत की जांच के लिए पश्चिम त्रिपुरा के एसपी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल गठित

अगरतला, 24 जुलाई (भा)। त्रिपुरा सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच के लिए पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की अगुवाई में तीन सदस्यीय दल का गठन किया है। इस संबंध में आज एक सरकारी आदेश जारी किया गया। भगोड़े हौरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े करीब 13,000 करोड़ रुपये के पीएमबी चोटले की सीबीआई जांच और 1984 के सिख विरोधी दंगों की फिर से जांच की अगुवाई कर चुके धनखड़ का शव सोमवार को पुलिस मुख्यालय स्थित उनके कार्यालय के शौचालय में फंदे से लटक हुआ मिला। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीजीपी अनुराग धनखड़ की अप्राकृतिक मृत्यु की जांच पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम करेगी। इस जांच में पश्चिम

त्रिपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ध्रुव नाथ और मामले के मौजूदा जांच अधिकारी एवं उप-निरीक्षक (पीएसआइ) शुभजीत देव, एसपी की सहायता करेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच के दौरान आवश्यकता पड़ती है, तो पुलिस अधीक्षक त्रिपुरा पुलिस की अपराध शाखा या किसी अन्य इकाई के अधिकारी को भी इस दल में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जांच में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध शाखा का सहयोग ले सकते हैं। शासकीय आदेश में कहा गया है कि जांच की प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) मंचक इप्पर को सौंपी जाएगी, जिसे आगे की समीक्षा के लिए त्रिपुरा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मेघालय के किसानों को नया बाजार, क्रिक कॉमर्स से बेंगलुरु के ग्राहकों तक पहुंच रहे अनानास

शिलांग, 24 जुलाई (एजें.)। मेघालय के बेहतरीन अनानास बेंगलुरु के क्रिक-कॉमर्स मार्केट में आ गये हैं। इससे ऑनलाइन ग्रासरी डिलीवरी सर्विस के जरिए राज्य की पहुंच शहरी ग्राहकों तक बढ़ गयी है। ये अनानास सीधे जिरा ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी से मंगaye जा रहे हैं और हवाई जहाज से बेंगलुरु भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच बेहतर बनाना और उनकी उपज के लिए अच्छी कीमत सुनिश्चित करना है। ये अनानास अपनी ज्यादा क्रिक्स वेल्यू (मिठास का पैमाना), मिठास और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। अधिकारियों ने

बताया कि यह पहल किसानों के लिए सीधे मार्केट से जुड़ने के रास्ते मजबूत करने और पारंपरिक सप्लाइ चेन पर निर्भरा कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। यह घटनाक्रम नयी दिल्ली के दिल्ली हाट में हुए चौथे मेघालय अनानास फेस्टिवल के बाद हुआ है, जहां सरकार के मुताबिक तीन दिनों में लगभग 30 मॉट्रिक टन ताजे अनानास बेचे गये थे। मार्केट तक पहुंच और बढ़ाने के लिये मेघालय सरकार ने फ्लिपकार्ट और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML) के साथ समझौते किये हैं, ताकि डिजिटल और संस्थागत प्लेयफ़ॉर्म के जरिये राज्य की कृषि उपज को बढ़ावा दिया जा सके।

समग्र शिक्षा के तहत त्रिपुरा विद्याज्योति स्कूलों में रोबोटिक्स, वीआर लैब शुरू करेगा

त्रिपुरा, 24 जुलाई (एजें.)। त्रिपुरा सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य भर के विद्याज्योति स्कूलों में रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और वरचुअल रियलिटी (वीआर)-आधारित लर्निंग शुरू करने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही इस पहल का मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों के अनुसार क्लासरूम की पढ़ाई में नयी टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। अनुभव-आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने और छात्रों की एनालिटिकल, क्रिएटिव और समस्या-समाधान क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विद्याज्योति स्कूलों में रोबोटिक्स और वीआर लैब बनायी जा रही हैं। इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए स्कूलों को जरूरी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जिसमें रोबोटिक्स उपकरण,

वीआर डिवाइस और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए जरूरी अन्य इलेक्ट्रॉनिक टूल शामिल हैं। इस पहल के हिस्से के तौर पर 20 जुलाई को शिशु बिहार स्कूल में शिक्षकों के लिए पांच दिन का क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस ट्रेनिंग का मकसद शिक्षकों को लैब को स्वतंत्र रूप से संचालने और क्लासरूम की पढ़ाई में नयी टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए तैयार करना है। सेशन के दौरान शिक्षकों को रोबोटिक्स, सेंसर-आधारित सिस्टम, बैटरी से चलने वाले मॉडल और ड्रोन ऑपरेशन का प्रैक्टिकल अनुभव मिल रहा है। उन्हें ड्रोन कंट्रोल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि बाद में छात्रों को इस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल के बारे में बताया जा सके। यह कार्यक्रम शिक्षकों को वीआर हेडसेट के इस्तेमाल से भी परिचित कराता है, जिससे

छात्र सिमुलेटेड माहौल के जरिये विज्ञान, इतिहास, अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव शरीर रचना विज्ञान जैसे विषयों में इमर्सिव (गहन अनुभव वाले) पाठों का अनुभव कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस्तेमाल और कार्यक्रम के सुचारु रूप से लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से क्लासरूम की पढ़ाई ज्यादा दिलचस्प बनेगी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ेगी, छात्रों में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें भविष्य के शैक्षणिक और कैरियर के अवसरों के लिए जरूरी स्किल्स से लैस किया जा सकेगा। अधिकारियों का यह भी मानना है कि इंटरैक्टिव लर्निंग तरीकों के ज्यादा इस्तेमाल से छात्रों की भागीदारी बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद मिल सकती है।

पूसी रेलवे ने ग्राहक अनुकूल पहलों के साथ माल परिवहन सेवाओं को दी गति

गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। पूर्वींतर् सीमांत रेलवे ने अपने नेटवर्क में माल ढुलाई राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ माल परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए कई ग्राहक-केंद्रित पहलें शुरू की हैं। इन उपायों का उद्देश्य ग्राहकों के लिए कार्गो की आवाजाही को अधिक तेज, कुशल और सुविधाजनक बनाना है। पार्सल हैंडलिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लामडिंग मंडल के अधीन नारंगी स्टेशन में 10 जून से आवक और जावक दोनों तरह के लीज्ड पार्सल की बुकिंग और हैंडलिंग, एसएलआर और पार्सल वैन में पार्सल स्पेस की अग्रिम बुकिंग और इंस्टैंड पार्सल ट्रैफिक शुरू किया गया है। माल परिवहन के संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक अन्य कदम के तहत कटिहार मंडल के अधीन बालुघाट-हिली सेक्शन पर नवनिर्मित ब्रॉड-गेज स्टेशनों



के लिए प्रभाय अंतर-दूरी को 23 जून से स्वीकृत कर दिया गया है, ताकि माल की प्रजातियों का पता चल सकता है। एक लुप्तप्राय भी दर्ज किया है। अलीपुरद्वार मंडल ने मक्का

के छह रैक (252 वैगन) लोड किए, जिससे माल ढुलाई राजस्व के रूप में 4.22 करोड़ रुपये की आय हुई। कटिहार मंडल ने मक्का के 39 रैक लोड किये, जिससे 23.53 करोड़ रुपये की आय हुई। लामडिंग मंडल ने भी

स्टोन चिप्स के 1,712 वैगन बुक कर, राजस्व में 6.97 करोड़ रुपये अर्जित करते हुए मजबूत स्थिति दर्ज की। इसके अलावा सीमेंट के 2,420 वैगन लोड किये गये और 9.89 करोड़ रुपये का राजस्व योगदान मिला, जबकि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स के 444 वैगन की लोडिंग से 4.08 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ। ये पहलें माल ढुलाई सुविधाओं का विस्तार करने, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कार्गो की कुशल आवाजाही सुनिश्चित कर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं। व्यापारों के लिएएल परिवहन के अधिक अवसरों का सुजन कर, एनएफआरए क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और विश्वस्वीय माल परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है।

शिरुई जंगलों में पहली बार दिखे लुप्तप्राय ढोल, वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि

इंफाल, 24 जुलाई (एजें.)। मणिपुर में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक अहम खोज के तहत, उखरुल जिले के शिरुई गांव के जंगलों में कैमरा ट्रैप के जरिये पहली बार लुप्तप्राय ढोल जिसे एशियाई जंगली कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है की मौजूदगी दर्ज की गयी है। यह रिकॉर्ड एनवायरनमेंटल फोर्स एट ग्रासरूट लेवल द्वारा किये गये वन्यजीव निगरानी सर्वेक्षण के दौरान बनाया गया। यह संगठन शिरुई गांव की जैव-विविधता को दर्ज करने और समुदाय के नेतृत्व में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

पिछले आठ वर्षों से ईएनएफओजीएल उखरुल जिले में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चला रहा है। इसमें स्कूलों, युवाओं, गांव के अधिकारियों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके वन्यजीवों की देखभाल और संरक्षण की संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है। पीढ़ियों से कई लोगों का मानना था कि शिरुई के आस-पास की पहाड़ियों में ढोल नहीं पाये जाते हैं। कैमरा ट्रैप फुटजे ने अब इस मुश्किल से दिखने वाले मांसाहारी जानवर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। इससे गांव के वन्यजीव रिकॉर्ड की बढ़ती सूची में एक और उल्लेखनीय प्रजाति जुड़ गयी है और शिरुई को वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने और मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण

जैव-विविधता वाले इलाकों में से एक के रूप में और अधिक पहचान मिली है।

यह सर्वेक्षण स्थानीय समुदाय, विशेषकर पमरेइथिंग के सहयोग से संभव हो पाया। पमरेइथिंग पहले शिकारी थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से संरक्षण के काम में समर्पित हैं। जंगल और वन्यजीवों की गतिविधियों के बारे में अपनी गहरी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कैमरा ट्रैप लगाने की जगह तय करने में अहम भूमिका निभायी, जहां आखिरकार ढोल की तस्वीर कैद हुई। शिकारी से संरक्षणवादी बनने का उनका सफर यह दिखाता है कि वन्यजीवों की सुरक्षा में स्थानीय समुदाय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभ सकते हैं। ढोल को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है और यह एशिया के सबसे ज्यादा खतरे वाले सामाजिक मांसाहारी जानवरों में से एक है। इनका अस्तित्व स्वास्थ्य जंगलों, शिकार की प्रचुरता और इंसानी दखल की कमी पर निर्भर



करता है। शिरुई में इस प्रजाति की मौजूदगी यह बताती है कि गांव के जंगल इस मुश्किल से दिखने

वाले शिकारी जानवर के लिए उपयुक्त आवास बने हुए हैं। इस खोज से शिरुई गांव का पारिस्थितिक

महत्व और भी बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में, इस इलाके से वन्यजीवों के कई उल्लेखनीय रिकॉर्ड सामने आये हैं, जो संकेत देते हैं कि यहां के जंगलों में अभी

भी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक

रूप से कोई जानकारी दर्ज नहीं की गयी है।

संरक्षणवादियों का मानना है कि अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है और लगातार शोध से इस अद्भुत इलाके में कई और दुर्लभ और महत्वपूर्ण

मांसाहारी जानवर की मौजूदगी दर्ज करने के अलावा,

कैमरा ट्रैप से मिले सबूतों से वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता और सराहना की जा रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में गांव की एक विशेष वन गश्ती टीम संरक्षित वन की नियमित निगरानी करती है ताकि शिकार और फंसाये जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके, जिससे वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलती है। इस खोज पर बात करते

हुए ईएनएफओजीएल के सह-संस्थापक और शिरुई गांव के निवासी पेट्रिक शांग ने कहा कि शिरुई गांव के निवासी के रूप में यह खोज भरे लिए बहुत मायने रखती है। यह हमारे जंगलों की समृद्धि और उन्हें बचाने के लिए हमारे समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस उपलब्धि का श्रेय शिरुई ग्राम प्राधिकरण और शिरुई के लोगों को जाता है, जिन्होंने शिकार पर प्रतिबंध लगाने और वन्यजीव संरक्षण का समर्थन करने का निर्णय लिया। उनकी सामूहिक कोशिशों के कारण हमारे जंगल वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह खोज सभी को आने वाली लुप्तप्राय वन विभाग जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे जिले में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। कन्पुनिटी-वेस्टड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के तहत शिरुई गांव

में फॉरेस्ट एरिया क्लोजर पहल ने संरक्षण प्रयासों को और मजबूत किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में गांव की एक विशेष वन गश्ती टीम संरक्षित

वन की नियमित निगरानी करती है ताकि शिकार और फंसाये जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके, जिससे वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलती है। इस खोज पर बात करते

भारत के लिए बढ़ता संकट दुनिया के लिए चेतावनी

मध्य-पूर्व में तेजी से बदलते युद्ध के हालात भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसके अलावा, लगभग 90 लाख भारतीय विभिन्न खाड़ी देशों में कार्यरत हैं और हर वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। यदि ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच जारी संघर्ष और व्यापक होता है तथा यमन के हूती विद्रोही लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों को अवरुद्ध करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, समुद्री परिवहन और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी, परिवहन लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह संघर्ष भारत के लिए केवल एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के लाल सागर स्थित बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा ने इस युद्ध को एक नये और अधिक खतरनाक चरण में पहुंचा दिया है। अब तक ईरान और इस्राइल के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष चल रहा था, लेकिन हूतियों की सक्रिय भागीदारी ने संकेत दे दिया है कि यह युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। हूती विद्रोही लंबे समय से ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और लाल सागर के महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों पर उनका प्रभाव है। यदि वे बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बाधित करते हैं, तो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।

यह संकट इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ईरान पहले से ही होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बनाये हुए है। यदि होर्मुज और बाब-अल-मंदेब दोनों समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो विश्व अर्थव्यवस्था को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। समुद्री माल ढुलाई महंगी होगी, तेल और गैस की कीमतों में उछाल आएगा तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला एक बार फिर बाधित होगी। कोविड महामारी के बाद जिस प्रकार दुनिया धीरे-धीरे आर्थिक स्थिरता की ओर लौट रही थी, उस पर यह युद्ध गंभीर आघात पहुंचा सकता है।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऊर्जा निर्यात पर आधारित है। यदि उनके निर्यात मार्ग बाधित होते हैं तो इसका प्रभाव केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अनेक देश इसकी कीमत चुकाएँगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ऊर्जा आयात महंगा होने से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और आम नागरिकों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले यह संघर्ष ईरान और इस्राइल तक सीमित था। बाद में अमेरिका सीधे इसमें शामिल हुआ। अब यमन, जॉर्डन और खाड़ी देशों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखायी दे रहा है। यदि यह स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो पूरा पश्चिम एशिया एक व्यापक युद्ध की आग में झूलस सकता है। इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र में छिड़े युद्ध वर्षों तक चलते हैं और उनके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं या कूटनीति का रास्ता अपनाते हैं। पिछले दो दशकों के अनुभव बताते हैं कि अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों ने सैन्य विजय तो दी, लेकिन स्थायी शांति नहीं ला सके। इसके विपरीत, लंबे युद्धों ने मानवीय संकट, आर्थिक क्षति और राजनीतिक अस्थिरता को ही जन्म दिया। ईरान भी प्रत्यक्ष युद्ध के साथ-साथ अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से जवाब देने की रणनीति अपना रहा है। ऐसे में केवल सैन्य कार्रवाई से समाधान निकलने की संभावना बहुत कम दिखायी देती है।

भारत ने हमेशा संवाद, संयम और शांतिपूर्ण समाधान की नीति का समर्थन किया है। वर्तमान परिस्थितियों में यही सबसे व्यवहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक शक्तियों को तत्काल युद्धविमम सुनिश्चित करने तथा सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध जितना लंबा चलेगा, उतना ही अधिक मानवीय संकट, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक तनाव बढ़ेगा।

आज दुनिया को हथियारों की नहीं, बल्कि कूटनीति की आवश्यकता है। यदि समय रहते इस संघर्ष को नहीं रोका गया, तो इसका प्रभाव केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही समय है जब सभी पक्ष शक्ति प्रदर्शन के बजाय संवाद, धैर्य और विवेक का मार्ग अपनाएं। स्थायी शांति का रास्ता युद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति और पारस्परिक विश्वास से होकर गुजरता है।

देव की डायरी : इस्तीफे की दृश्य व अदृश्य प्रदर्शनी

देव प्रकाश चौधरी
हले आदमी से पूछा जाता था, क्या करते हैं? फिर पूछा जाने लगा, कहाँ रहते हैं? अब नया जमाना है। सबसे पहला सवाल होगा, इस्तीफा दिया कि नहीं? आदमी का चरित्र, संस्कार, अनुभव, सब बाद में देखे जाएंगे। पहले उसका इस्तीफा देखा जाएगा। जिसने एक बार दिया, वह नौसिखिया माना जाएगा। जिसने कई बार दिया, वह अनुभवो कहलाएगा।
आने वाले समय में बायोडाटा भी बदलेगा। नाम, पता, शिक्षा के बाद एक नया खाना होगा-अब तक दिये गये इस्तीफा। उसके नीचे एक और कॉलम होगा, जिसमें किसी एक पर टिक लगाना होगा- स्वीकार हुए, लंबित, विचाराधीन और केवल चर्चा में रहे। इतिहास भी नये सिरे से लिखा जाएगा। पहले लिखा जाता था कि अमुक व्यक्ति ने देश के लिए क्या किया? अब लिखा जाएगा कि उसने कितनी बार इस्तीफा दिया, कितनी बार देने की घोषणा की और कितनी बार देने की इच्छा व्यक्त की।
धीरे-धीरे वह दिन भी आएगा जब आदमी अपने नाम से नहीं, अपने इस्तीफे से पहचाना जाएगा। कुछ लोग इतने प्रसिद्ध होंगे कि उनका परिचय बस इतना होगा- अरे, वही... जिनका इस्तीफा पिछले स्रह महीने से रास्ते में है। ऐसे लोग लोकतंत्र के वरिष्ठ कलाकार माने जाएँगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ललित कला अकादमी को अपना पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। मूर्तिकला, चित्रकला, छापाकला, लोककला के साथ एक नया विभाग खोलना ही होगा-इस्तीफा कला। कला का विकास समाज के साथ होता है। जिस समाज

। संपादकीय । संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

ललित गर्ग

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के आंदोलन के दौरान जो तनाव, टकराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं, वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं कहे जा सकते, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं पर रखी गयी है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा, टकराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित होती है।

राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लोक प्रकरण को लेकर चल रहे घटना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठना और संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण, अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं, उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसी अराजक परिस्थितियां पैदा करने को उजावले हैं। सरकार की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गयी कार्रवाई से, कुछ कमियों के बावजूद, इस बड़े संकट को टाल दिया गया, अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और अशांति की चपेट में आ सकती थी। देश पहले भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लगभग सौ दिनों

विनोद पाठक

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगों, शिकायतों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। भारत में जंतर-मंतर लंबे समय से ऐसे जनआंदोलनों का प्रतीक रहा है, जहां विभिन्न वर्ग अपनी समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखते रहे हैं।

विरोध, प्रदर्शन और नारे लोकतंत्र की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन इन सबके बीच संवाद की मर्यादा और भाषा का संयम भी उतना ही आवश्यक है।

अभी जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में जिस प्रकार की अभद्र, अश्लील और आक्रामक भाषा सुनाई दी, उसने केवल एक आंदोलन की शैली पर ही नहीं, अपितु हमारे सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े किये हैं। किसी भी घटना का मूल्यांकन कुछ वीडियो के आधार पर पूरे समाज पर आरोप लगाकर नहीं किया जा सकता, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। चिंता केवल इस बात की नहीं है कि गालियां दी गईं, बल्कि इस बात की है कि उन्हें विरोध की वैध भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है।

भारत के छात्र और युवा आंदोलनों का इतिहास बताता है कि यहां विचारों की लड़ाई तर्क, संगठन और वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर लड़ी जाती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल के विरोध और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों तक अनेक आंदोलनों

तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि सड़क पर टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी मांगें भी समाज की सहानुभूति खो बैठती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ग, विशेषकर युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है।

इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका

उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश में एक सकारात्मक बहस प्रारंभ हुई। इसके विपरीत जहां-जहां आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, वहां उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गयी। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी शक्तियां हैं, जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें अराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंता केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन यदि असहमति के मंच पर राष्ट्रविरोधी, अराजक अथवा हिंसक तत्व सक्रिय हो जाएं, तो उन्हें नियंत्रित करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता की स्वतंत्रता नहीं हो सकता।

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक स्थल है। यदि इन दोनों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ व अराजकता का दृश्य निर्मित होता है, तो यह केवल राजधानी की घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र की छवि को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन अधिक आक्रामक है, बल्कि इस बात में है कि कौन अधिक संयमित और उत्तरदायी है। राजनीतिक कर्मचारी को भी आत्ममंथन करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि दोनों के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा, तो लोकतंत्र टकराव का अखाड़ा बन जाएगा। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना भी है। लोकतंत्र में किसी की पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती, यहां अंततः संवाद, सहमति और समाधान ही सबसे बड़ी जीत होती है।

छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा हैं। यदि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन

केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

डिजिटल क्रांति ने भारतीय समाज को अभूतपूर्व अवसर दिये हैं। इंटरनेट ने शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति के नये द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आयी हैं। सोशल मीडिया मंचों की एल्गोरिदमिक संरचना अक्सर उत्तेजक, विवादास्पद और आक्रामक सामग्री को अधिक दृश्यता देती है। ऐसे वातावरण में संयमित और तथ्यपरक संवाद की अपेक्षा तीखी भाषा अधिक तेजी से फैलती है।

परिणामस्वरूप कई बार युवा यह मानने लगते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए आक्रामक भाषा आवश्यक है। मनोरंजन उद्योग और डिजिटल सामग्री का प्रभाव भी इस विमर्श का हिस्सा है। फिल्मों, वेब सीरीज, स्टैंड-अप कॉमेडी और सोशल मीडिया कंटेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग पहले की तुलना में अधिक सामान्य दिखायी देता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल यही कारण है, लेकिन यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि लोकप्रिय संस्कृति समाज की भाषायी आदतों को प्रभावित करती है। विशेष रूप से किशोर और युवा वर्ग अपने पसंदीदा कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स व प्रभावशाली व्यक्तियों की भाषा और व्यवहार से प्रभावित होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार मौलिक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यही संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और दूसरों

होगी, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाये। वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा उनके आंदोलन की सबसे बड़ी शत्रु है। पत्थर और लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं करते, वे केवल संवाद के पुलों को तोड़ते हैं। आज आवश्यकता लोकतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की है। हमें ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें विरोध हो, लेकिन वैमनस्य न हो। मतभेद हों, लेकिन मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन हिंसा न हो। लोकतंत्र में बहस जितनी प्रबल होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। किंतु बहस का स्थान यदि हिंसा ले लेगी, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होगी। जंतर-मंतर से संसद तक जो कुछ हुआ, उसे लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। यह किसी परिपक्व राजनीतिक सोच का भी परिचायक नहीं है। राष्ट्र निर्माण का मार्ग टकराव नहीं, सहयोग है। हिंसा नहीं, सहमति है। उग्रता नहीं, उदारता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने-अपने अग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें।

आज देश को ऐसे नेतृत्व और ऐसी जनचेतना की आवश्यकता है, जो संवाद को संघर्ष से ऊपर रखे। सरकार उदारता और संवेदनशीलता दिखाये, आंदोलनकारी संयम और अनुशासन अपनाएं तथा राजनीतिक दल अल्पकालिक लाभ के बजाय लोकतंत्र की दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दें। यही भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की वास्तविक पहचान भी है और भविष्य की आवश्यकता भी। अंततः यही कामना की जानी चाहिए कि जिन शक्तियों के कारण आंदोलनों में हिंसा और टकराव का वातावरण बनता है, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। सभी पक्ष संवाद की मेज पर बैठें, अपनी बात तर्क, तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ रखें तथा समाधान का मार्ग खोजें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय किसी पक्ष की जीत नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब विरोधी पक्ष भी एक-दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही आदर्श लोकतंत्र की पहचान है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत बुनियाद भी है।

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।
डिजिटल क्रांति ने भारतीय समाज को अभूतपूर्व अवसर दिये हैं। इंटरनेट ने शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति के नये द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आयी हैं। सोशल मीडिया मंचों की एल्गोरिदमिक संरचना अक्सर उत्तेजक, विवादास्पद और आक्रामक सामग्री को अधिक दृश्यता देती है। ऐसे वातावरण में संयमित और तथ्यपरक संवाद की अपेक्षा तीखी भाषा अधिक तेजी से फैलती है।

परिणामस्वरूप कई बार युवा यह मानने लगते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए आक्रामक भाषा आवश्यक है। मनोरंजन उद्योग और डिजिटल सामग्री का प्रभाव भी इस विमर्श का हिस्सा है। फिल्मों, वेब सीरीज, स्टैंड-अप कॉमेडी और सोशल मीडिया कंटेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग पहले की तुलना में अधिक सामान्य दिखायी देता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल यही कारण है, लेकिन यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि लोकप्रिय संस्कृति समाज की भाषायी आदतों को प्रभावित करती है। विशेष रूप से किशोर और युवा वर्ग अपने पसंदीदा कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स व प्रभावशाली व्यक्तियों की भाषा और व्यवहार से प्रभावित होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र में असहमति का अधिकार मौलिक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यही संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और दूसरों को संरक्षित करने का दायित्व भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

लोकतंत्र की भाषा या भाषा का पतन केवल एक सुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल दर्शन रहा है। ज्ञान के साथ विनम्रता, असहमति के साथ संयम और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध, यही शिक्षा की वास्तविक कसौटी है।

संक्षिप्त समाचार

जीएसटी विवादों के निपटारे के लिए आगरा में करें अपील, 15 जिलों को मिलेगा फायदा

आगरा, एजेंसी। कन्ददाताओं की सुविधा के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की आगरा खंडपीठ का संचालन शुरू हो गया है। उप पंजीयक अजय लवानिया की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है। राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत इस खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में कुल 15 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें आगरा, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़), औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा हैं। पीठ सीजीएसटी एवं सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपीली की



फाइलिंग व सुनवाई करेगी। अपील दाखिल करने में सहायता के लिए जीएसटीएटी पोर्टल पर ई-फाइलिंग संबंधी नियम उपलब्ध हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क किया जा सकता है। यह खंडपीठ सिकंदरा स्थित वैशाली कॉलोनी के अस्थायी पते से कार्य कर रही है। इसे क्रॉस रोड मॉल, सिकंदरा के स्थायी पते पर स्थानांतरित किया जाएगा।

फिर शुरू होगा मानसूनी बारिश का सिलसिला

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में बारिश ने छोटा सा ब्रेक लिया है। छिटपुट बारिश को छोड़ दे तो आने वाले 26 जुलाई तक किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि लखनऊ में गुरुवार की शाम को कुछ इलाकों में बारिश हुई। मानसूनी बारिश के फिलहाल कमजोर रहने के बाद 26 जुलाई से फिर से मौसमी बदलाव की आहट है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 26 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसूनी बारिश मद्धिम पड़ेगी। हालांकि इस बीच बुंदलखंड और कुछ दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश की परिस्थितियां रहेगी। बृहस्पतिवार को इटावा में सबसे अधिक 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और आजमगढ़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं किया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को मानसून ट्रंक उत्तर की ओर खिसकेगा। इसके प्रभाव से पूर्वांचल में फिर बारिश शुरू होगी और 29 जुलाई तक तराई समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

सावनमें शिवभक्तों की राह आसान करेगी वक्यूआरटी

वाराणसी , एजेंसी। सावन में काशी आने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रख नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए निगम ने क्रिक रिसॉर्स टीम (वक्यूआरटी) के गठन का निर्णय लिया है। यह टीम कांवर मार्ग की साफ-सफाई, सीवर ओवरफ्लो, पेयजल और मार्ग प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करेगी। बृहस्पतिवार को सिगरा स्मार्ट सिटी सभागार में मेयर अशोक कुमार तिवारी ने तैयारियों की समीक्षा की। मेयर ने श्रीकाशी विधान्या धाम समेत शहर के सभी प्रमुख शिवालयों और गंगा घाटों विशेषकर दशाधमेध, शीतला, राजेंद्र प्रसाद और अरसी घाट को जोड़ने वाली गलियों में सुबह-शाम अनिवार्य रूप से सफाई का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं के मार्ग में आवारा पशु न दिखे और अतिक्रमण से मुक्ति मिले। शहर को भिक्षामुक्त काशी बनाने के लिए भी अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। सीवर जाम की समस्या से निपटने के लिए जेटिंग मशीनों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। सावन में पंचकोशी यात्रा का विशेष महत्व होता है। इसे ध्यान में रख पंचकोशी मार्ग की सड़कों की मरम्मत और व्यापक सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवरियों के लिए लगाए जाने वाले शिदिरों में निगम की ओर से शुद्ध पेयजल, डस्टबिन, चूना छिड़काव और अस्थायी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान सावन के दौरान और सख्त रहेगा। काशी विधान्या धाम से तेकर सारंगनाथ तक रहेगी विशेष नजर निगम ने सावन के दृष्टिगत शहर के प्रमुख शिवालयों की सूची तैयार की है जहां विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

जिसे बच्चा समझकर किया भरोसा.. उसी ने दो लोगों के साथ मिलकर नेपाल की महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म

औरंगाबाद, एजेंसी। बिहार के औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर रहकर चाय बेचने वाले एक नेपाल निवासी व्यक्ति की पत्नी के साथ तीन अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है. अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के पास एक जर्जर भवन में घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. पुलिस ने महिला का सदर हॉस्पिटल में मेडिकल कराया है.

दो आरोपी हैं टोटो चालकर: गिरफ्तार लोगों की पहचान हो गई है. एक नगर थाना क्षेत्र का है तो दूसरा नवादा का रहने वाला है. अभिषेक और राकेश औरंगाबाद में ही टोटो चलाते हैं. इन्होंने कहीं ऐसी और किसी घटनाओं का अंजाम तो नहीं दिया है, पुलिस इस मामले की भी छनबीन कर रही है.

3 साल पहले हुई थी दूसरी शादी: सामूहिक दुष्कर्म की शिका महिला नेपाल की रहने वाली है. उसका पति औरंगाबाद में रहकर घूम- घूमकर चाय बेचने का काम करता है. पहली



पत्नी की मौत के बाद पीड़ित महिला से उसने तीन साल पहले दूसरी शादी की थी. पहली पत्नी से उसे चार बच्चे हैं. बच्चों को घुमाने के बहाने ले गए आरोपी: जानकारी के अनुसार, मंगलवार को शाम पांच बजे महिला घर के बाहर खड़ी थी तभी नाबालिग आरोपी जोकि उसके बगल में ही रहता था, बच्चों को शहर घुमाने के बहाने अपने टोटो पर बिठा लिया. टोटो पर पहले से ही जीतू उर्फ पाली और अभिषेक बैठे हुए थे. इधर-उधर घूमते हुए आरोपियों ने शाम कर दिया. जब अंधेरा बढ़ने लगा तब वे लोग एक शिव मंदिर के पास पुराने जर्जर भवन में ले गए, जहां तभी ने उसके साथ बाजी-बारी से जबरदस्ती की. बात नहीं मानने पर उसके

साथ मारपीट भी की गई.

कार्टून लगाकर बच्चों को दिया मोबाइल: महिला से दुष्कर्म करने से पहले आरोपियों ने बच्चों को मोबाइल में कार्टून फिल्म लगाकर दे दिया. बच्चे टोटो में ही बैठकर कार्टून फिल्म देख रहे थे. जबकि आरोपियों ने खंडहर में ले जाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

महिला को 200 रुपये देकर फरार: सामूहिक दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपी पीड़ित नेपाल की महिला को पानी टंकी के पास छोड़कर फरार हो गए. जाते समय उसे आरोपियों ने 2 सौ रुपए दिए.

पुलिस ने किया गिरफ्तार: घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को दी. पति ने नगर थाना में जाकर थाना प्रभारी से शिकायत की. शिकायत मिलते ही नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई. टीम ने लगातार छपेमारी करते हुए किशोर सहित दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सिर्फ नाम की होगी सीईओ की पॉवर, असली ताकत महासचिव के पास

लखनऊ , एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति होने के बाद भी ट्रस्ट की वास्तविक प्रशासनिक और नीतिगत कमान महासचिव के ह्थ में ही रहेगी। ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नियमावली के मुताबिक सीईओ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के बजाय महासचिव के अधीन कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, कार्यों की समीक्षा और बजट पर अंतिम मंजूरी का अधिकार भी महासचिव के पास ही रहेगा। ऐसे में ट्रस्ट की सबसे प्रभावशाली जिम्मेदारी महासचिव के पास ही बनी रहेगी।

ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक महासचिव ट्रस्ट का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। मंदिर

की संपत्तियों, बैंक खातों और कानूनी दस्तावेजों पर अंतिम नियंत्रण उसी के पास रहता है। मंदिर के विकास, बड़े निर्माण कार्य, वित्तीय निवेश, धार्मिक आयोजनों और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी महासचिव को ही प्राप्त है। अदालतों, केंद्र व राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के सामने ट्रस्ट का आधिकारिक प्रतिनिधित्व भी वहीं करता है। इसके अलावा सीईओ की नियुक्ति, उसके कार्यों का मूल्यांकन और ट्रस्ट की ओर से तैयार किए गए बजट को मंजूरी देने की जिम्मेदारी भी महासचिव की होगी।

सीईओ की भूमिका मुख्य रूप से मंदिर के दैनिक प्रशासन तक सीमित रहेगी। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, वीआईपी

मूवमेंट, कर्मचारियों की निगरानी, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन और



पुलिस के साथ समन्वय, ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत बजट के अनुरूप खर्च, आय-व्यय का पूरा हिसाब रखना उसकी जिम्मेदारी होगी। त्योहारों और विशेष अवसरों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी सीईओ के जिम्मे

रहेगी। सीईओ को समय-समय पर अपने सभी कार्यों का ब्योरा महासचिव को देना होगा और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा भी महासचिव करेंगे। यानी सीईओ मंदिर के संचालन का पेशेवर प्रशासक होगा, लेकिन ट्रस्ट की नीतिगत दिशा, वित्तीय नियंत्रण और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति महासचिव के पास ही केंद्रित रहेगी। यही वजह है कि सीईओ की नियुक्ति के बाद भी ट्रस्ट में सबसे प्रभावशाली पद महासचिव का ही माना जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को हुई बैठक में भी महासचिव के नाम पर मुहर नहीं लग सकी। इसे लेकर लगातार मंथन जारी है। महासचिव के नामों पर किसी न किसी स्तर पर पेच फंस रहा है। दिल्ली स्तर से नाम

फाइनल होगा या फिर लखनऊ की राय अहम होगी, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों स्तरों पर इसे लेकर जद्दोजहद जारी है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। सभी नाम वरत से तय किए गए थे। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय को सबसे अहम महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी। चढ़ावा चोरी मामले में उनका इस्तीफा हो चुका है। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। तब बताया गया था कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में नए महासचिव का चयन किया जाएगा। तब तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बताया जा रहा है।

रस्साकसी महिला वर्ग में प्राथमिक विद्यालय डोरिया की टीम रही प्रथम

बरेली , एजेंसी। रूहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर गोद लिए गए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बृहस्पतिवार को आयोजित इन प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक खेल खो-खो, रस्साकसी और संपोलिया (पिट्टु) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की।

रस्साकसी महिला वर्ग में प्राथमिक विद्यालय डोरिया की टीम ने ललितला, जोया, सायमा, माही, अलीश, आसिया, अनम, प्राथी, अल्लाना, आलीया, अंजु, सोफिया के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में समद, तीसफ, तहसीम, इशा अली, बिलाल, तसलीम, अरमान, मो. आरिस, तैमूर, गौरव, अदनान, हार्दिक, हुसैन और अल्लमस की टीम विजेता बनी। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय डोरिया ने खो-खो के बालक व बालिका दोनों वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। संपोलिया में पुरुष वर्ग से अमित, राकेश, अनश, पीयूष, ऋषिभ व तैमूर तथा महिला वर्ग से जौनस, मन्नत, सोफिया, श्रेया, आरसी व अनाया नूर की टीम अव्वल रही।

उच्च प्राथमिक विद्यालय डोरिया का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। रस्साकसी पुरुष वर्ग में अरसलाल रजा, अरशद, खालिद, शादाब, अरमान, लक्ष्मण, ह्रदीन अली, जैनुल, माहित, फैजाल और सैफ की टीम ने बाजी मारी। महिला वर्ग में खूशबू, कीर्ति, आलिय, रजनवी, प्रियांशी, प्रियंका, मोहिनी, रसुति, मनवी और आरोही प्रथम स्थान पर रहीं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय डोरिया ने खो-खो तथा संपोलिया के पुरुष व महिला दोनों वर्गों की ट्रॉफी अपने नाम की।

पूर्व माध्यामिक विद्यालय बेनौराम की ओर से खो-खो महिला वर्ग में शिल्पी, तान्या, महिमा, अनामिका, मीनाक्षी, खुशी, निशा, अर्याशी, अमृता व नैन्सी ने पहला स्थान हासिल किया। रस्साकसी पुरुष वर्ग में लव, आदित्य, यश, कपिल, हिमांशु, मुनींद्र, मिथिलेश, कमल, शिव, अनमोल व अखिलेश की टीम विजयी रही। संपोलिया के पुरुष वर्ग में मुनींद्र, लव, शल्प, सिद्धार्थ, अनुराग और अंश ने बाजी मारी। प्राथमिक विद्यालय लालपुर की टीम ने संपोलिया पुरुष वर्ग में अभिनव, प्रशांत, अंकुश, कुश और ऋतिक के शानदार खेल से प्रथम स्थान पाया। रस्सा-कसी पुरुष वर्ग में प्रशांत, राहुल, कुश, ऋतिक, चिराग, राजीव, रामनिवास व वंश की टीम विजेता बनी।

खेतों तक पहुंचा क्रोमियम युक्त कचरा

अफसर बोले- इसके बाद हटाया जाएगा मलबा

कानपुर , एजेंसी। कानपुर के पुरवामीर गांव में अवैध रूप से डाला गया क्रोमियम युक्त कचरा अब खेतों तक पहुंच गया है। वनस्पति विशेषज्ञों का कहना है कि इस जहरीले कचरे से पैदावार को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा पर उपजी सब्जियां, फसलों और अनाज से क्रोमियम शरीर में पहुंच जाएगा। यह सेहत को काफी नुकसान पहुंचाएगा। वहीं, अफसर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस हरे रंग के कचरे को हटाने की बात कह रहे हैं। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं।

महाराजपुर के पुरवामीर गांव में चार दिन पहले रात के अंधेरे में डंपरों से क्रोमियम युक्त रासायनिक कचरा डाला गया था। इसके बाद प्रशासन, पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपी पीसीबी) की कानपुर नगर और प्रयागराज की टीम ने मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की। साथ्य जुटाने के साथ ही बोर्ड की दोनों टीमों ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। टीमों ने कहा था कि यह कचरा सेहत और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है।

यूपी पीसीबी कानपुर नगर के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन के अनुसार पुरवामीर में फेंका गया मलबा शुरुआती जांच में क्रोमियम सल्फेट का प्रतीत हो रहा है। वहां से लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 24 जुलाई को आएगी। इससे स्थिति स्पष्ट होगी। आशंका है कि फतेहपुर जिले में क्रोमियम सल्फेट की किसी फैक्टरी से यह घातक रसायन युक्त मलबा कानपुर-प्रयागराज राष्टीय राजमार्ग से सटे इस गांव में फेंका गया।

यह गांव फतेहपुर जिले की सीमा से मात्र ढाई किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि खुले में पड़े इस मलबे से निकलने वाली बदबू और जहरीली हवा के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। गांव के लोगों का साफ कहना है कि जांच चलती रहे लेकिन पहले इस मलबे को वहां से हटाकर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित



कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस कचरे से जमीन के बंजर होने का भी खतरा है।

यह रासायनिक कचरा रात के अंधेरे में चोरी छिपे फेंका गया है। अभी तक इसको हटवाया नहीं गया है। उस जगह रहने वाले कई लोगों ने शिकायत की है। हरा कचरा बेहद बदबू कर रहा है। वहां थोड़ी देर खड़े होने से मेरा सिर चकराने लगा। यदि इसको जल्द हटवाया नहीं गया तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा। -जितेंद्र सिंह गीतम, ग्राम प्रधान जिस जगह पर यह कचरा डाला गया है, वहीं मेरा चट्टा है। चट्टे में 50 बैरस हैं। जिस दिन से यह कचरा डाला गया है, उस दिन से मवेशियों को बांधकर रखना पड़ रहा है। उस जगह पानी न पिलाकर अब दूर ले जाना पड़ता है। कचरा नहीं हटवाया गया तो बारिश में और ज्यादा फैलेगा। कचरा डाले कई दिन बीत गए हैं। इससे बहुत बदबू आ रही है। आसपास खड़ा होना तो दूर सांस लेना भी दुभर है। लोगों के बीमार होने का खतरा है।

पाँक्सो आरोपी ने जेल में की खुदकुशी, मां से मुलाकात के बाद उठाया खौफनाक कदम, सिपाही सस्पेंड



लिया और ऊपर ग़िल में गमछ बांधकर खुदकुशी कर ली. जब तक जेल प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तब तक काफी देर हो चुकी थी. ग़िल काटकर उसे नीचे उतारा गया और तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया.

मां से मुलाकात के बाद उठाया कदम : सूत्रों के अनुसार घटना से कुछ समय पहले कैदी की मां उससे मुलाकात कर वापस लौटी थी. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह की बातचीत भी चल रही थी. हालांकि, मां के जाने के

बाद अचानक कैदी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है. जेल सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि घटना से पहले वह सामान्य व्यवहार कर रहा था और दोपहर का भोजन भी किया था.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया : जेल प्रशासन इत्रा कैदी को ऑक्सिजन सपोर्ट के साथ इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोपहर 3:57 बजे क्लीनिकल और ईसीजी जांच के आधार पर उसे मृत घोषित कर दिया, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सौंप दिया गया.

चाबी लेकर खुद ही किया दफ्न लॉक : जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सिपाही नीतीश कुमार बाई खोलने के लिए चाबी लेकर आया था. इसी दौरान कैदी ने उससे चाबी लेकर सीढ़ी का गेट बंद कर लिया और ऊपर जाकर फांसी लगा ली. घटना के बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

फर्जी तरीके से पेंशन लेने के आरोप लगाने वालों पर करूंगी मुकदमा : माकपा नेता

कन्नूर, 24 जुलाई (भा)। मावर्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की वरिष्ठ नेता पीके श्रीमति ने आज कहा कि केवल माफि मांग लेना पर्याप्त नहीं है और वह उनके खिलाफ पूर्व विधायक की पारिवारिक पेंशन लेने को लेकर झूठा अभियान चलाने वालों पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। कुछ ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने कथित आरटीआई दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि पीके श्रीमति पूर्व विधायक पीआर कृष्णन के नाम पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं।

इसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि पीआर कृष्णन के परिवार ने कल स्पष्ट किया कि पेंशन की वास्तविक लाभार्थी उनकी पत्नी हैं और उनका नाम भी पीके श्रीमति है। परिवार ने बताया कि माकपा नेता के खिलाफ यह आरोप केवल इसलिए लगा, क्योंकि उनका नाम पूर्व विधायक की पत्नी के नाम से मेल खाता है। पीआर कृष्णन कांग्रेस के नेता थे और वर्ष 1954 से 1956 के बीच त्रावणकोर-कोचीन विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। पूर्व मंत्री ने आज

झारखंड में गोलीबारी : अपराधियों के गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

हजारीबाग, 24 जुलाई (भा)। झारखंड के हजारीबाग जिले में आज पुलिस के साथ हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद एक आपराधिक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये दोनों आरोपियों में से एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। बड़कागांव के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 'राहुल दुबे' गिरोह के दो सदस्य मोटरसाइकिल पर सवार होकर केरेंडारी क्षेत्र स्थित एक कोयला औद्योगिक इकाई से रांदारी वसूलने जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने इलाके में छापेमारी की। एसडीपीओ ने कहा कि बुकरू ट्रांसपोर्टिंग रोड के पास जब उन दोनों को रोका गया, तो उन्होंने पुलिस टीम का सामना किया और जवानों पर गोली चलायी, जिससे पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों में से एक के पैर में गोली लगी।

पूर्वी दिल्ली में कार सवार की चाकू मारकर हत्या, जांच जारी

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भा)। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में एक कार सवार व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी विनोद नगर निवासी विजय कुमार को कल रात ८. हेडगेनार अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि रात करीब नौ बजे पीसीआर को सूचना मिली कि कृष्णा नगर की मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुमार की कार सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़ी मिली। तक रक स्थानीय लोग घायल को अस्पताल पहुंचा चुके थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरिस्टिक और अपराध जांच दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा हमलावर की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।

यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस झूठे प्रचार अभियान से उन्हें गहरी व्यक्तिगत पीड़ा हुई है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब मेरे परिवार के लोग और दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि उन्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही हूं। किसी भी परिवार को झूठी खबरों की वजह से ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। श्रीमति ने बताया कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, गृह मंत्री रमेश चेल्लिथला,

राज्य पुलिस प्रमुख और केरल महिला आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआती शिकायतें हैं। अब मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। मेरे वकील मेरे साथ हुई गंभीर सार्वजनिक बदनामी और मेरी प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा तैयार कर रहे हैं। यह पूछने पर कि अगर आरोप लगाने वाले लोग माफी मांग लें, तो क्या मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, जिसपर श्रीमति ने कहा कि सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा।

नीट समाप्त कर 12वीं के अंकों के आधार पर हो मेडिकल दाखिले : एलंगोवन



चेन्नई, 24 जुलाई (भा)। द्रविड़ मुनेत्र कणम (द्रमुक) के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने राष्ट्रीय पात्रा-स-प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर अपनी पार्टी का खूब दोहराते हुए आज कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला पूरी तरह से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए। एलंगोवन ने कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के खूब की भी आलोचना की। एलंगोवन ने कहा कि नीट ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

एलंगोवन ने नीट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल दाखिले का आह्वान किया।

पृष्ठ 1 का शेप

अलावा शीर्ष ही केंद्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल असम भेजा जाएगा। यह दल राज्य सरकार के साथ बैठक करने के साथ-साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन करेगा, जिसके आधार पर राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय भी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये त्वरित कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि और विज्ञा प्रशासन मिलकर बाढ़ व बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में प्रभावित 2,023 गांवों के लिए 255 राहत शिविर स्थापित किये गये हैं। विशेष रूप से शिवसगर, चराईव, जोराहत, गोलाघाट, होजाई, कामरूप, कामरूप महानगर, डिब्रुगढ़, नागंव, कबी आंगलांग और तिनसुकिया जिलों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। सोनोवाल ने असम के सभी गाँों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों से इस संसट की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मानवीय जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों के बल पर ही इस आपदा से उबरा जा सकता है तथा केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सार्व आश्यक सहयोग प्रदान करती रहेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने...

संगठित कदाचार पर रोक लगाना है। सूत्रों ने बताया कि संशोधित विधेयक के सोमवार को संसद में पेश किया जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कल मध्यरात्रि को एक वीडियो संदेश में कहा था कि सोमवार को जब संसद के मानसून सत्र का दूसरा सत्राह शुरू होगा तो प्रश्नपत्र लोक के मामलों में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक लाया जाएगा। और हम उसे जल्द से जल्द पारित करने की कोशिश करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में की गयी, जब कॉन्ग्रेस जनता पार्टी (कांजपा) शिक्षा मंत्री धर्मंद प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लोक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना देी मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूरा मंत्रिमंडल प्रधान के समर्थन में खड़ा है और सरकार द्वारा विपक्ष की उनके इस्तीफे की मांग को स्वीकार करने की संभावना नहीं है। विपक्ष 20 जुलाई को अपनी मांगों के समर्थन में संसद तक मार्च निकालने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादती के लिए प्रधानमंत्री से माफी की मांग भी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में सुधारों से जुड़े सभी मुद्दों पर भी काम कर रही है। एनटीए चिकित्सा प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) यानी नीट-यूजी आयोजित करती है। वही दूसरी ओर नीट प्रश्नपत्र लोक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जायेगी। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनटीए में व्यापक बदलाव किंे जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाये जाएंगे। हम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रश्नपत्र लोक और सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन में आई गड़बड़ियों को लेकर पैदा हुए छात्रों के आक्रोश के कारण शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है।

नीट प्रश्नपत्र लोक...

डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के लागू करने तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की परीक्षा प्रणाली से जुड़े मॉडल को अपनाने के संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। शिक्षा मंत्रालय ने सात-सदस्यीय राधाकृष्णन समिति का गठन नीट-यूजी प्रश्नपत्र लोक के बाद परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार संबंधी सिफारिशें देने के लिए किया था। याचिकाओं में से एक में नीट-यूजी आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन अथवा उसके स्थान में मंत्रिमंडल प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए अधिक सशक्त और स्वायत्त निष्का गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मेहता ने कहा कि इस मामले में कुछ नये घटनाक्रम हुए हैं और केंद्र सरकार बाढ़ विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसमें राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अलावा उठाये गये अन्य कदमों की जानकारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हम राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से भी आगे बढ़कर कदम उठा रहे हैं। मैं आपको आश्वासन करता हूं कि सरकार अपेक्षा से कहीं अधिक प्रयास कर रही है और हर चीज की खोज-खज् खज् स्तर पर निगरानी की जा रही है। मेहता ने यह भी कहा कि दो वर्ष पहले भी ऐसी तरह का मामला सामने आया था और उस समय प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर उच्च परीवहन तक की पूरी प्रणालि अदालत के समक्ष स्पष्ट की गयी थी। इसपर पीठ ने कहा कि सरकार ने नीट-यूजी की पुनःपरीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों के परिवहन में वायुसेवा की मदद दी थी, लेकिन ऐसे उपाय केवल तदर्थ व्यवस्था है। न्यायमूर्ति नरसिन्हा ने कहा कि वर्षों से चली आ रही तदर्थ व्यवस्थाओं ने परेशानी खड़ी की हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया के लिए एक स्थायी और संस्थागत

मुंबई विरोध प्रदर्शन : महिला से बदसलूकी के आरोपों को मुंबई पुलिस ने खारिज किया

मुंबई, 24 जुलाई (भा)। मुंबई पुलिस ने आज कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला के साथ कथित रूप से बदसलूकी करने का वीडियो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पुलिस ने सफाई दी कि अधिकारी वास्तव में एक पुरुष प्रदर्शनकारी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी वह महिला अनजाने में बीच में आ गयी। यह वीडियो तब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया, जब कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इसे

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी का बयान

शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं आरआरआर केंद्र का शुभारंभ



जयपुर, एजेंसी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में गुरुवार को जयपुर जिले के फागी ब्लॉक में शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं आरआरआर (रिड्यूस, रीयूज, रिसायकल) केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र जिला परिषद जयपुर, फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख रूपए के सीएसआर सहयोग तथा शक्ति संगम संस्था की सहभागिता से स्थापित किया गया है। यह केंद्र ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, आजीविका संवर्धन तथा हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकारी प्रयासों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिनोवा कैपिटल के प्रबंध निदेशक मोहित साहनी ने कहा कि महिलाओं का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि यह केंद्र भविष्य में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनेगा। केंद्र में हाई स्पीड सिलाई मशीन, पीको मशीन, ओवरलॉक मशीन सहित आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। समारोह के दौरान वेस्ट टू वेल्थ थीम पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार अपसर्पिकल उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पुराने कपड़ों से तैयार बैग, कैंप, चरमे के कवर, यूटिलिटी पाउच, मैट, टोकरियां, हस्तशिल्प उत्पाद तथा पर्यावरण अनुकूल राखियों आकर्षण का केंद्र रहीं।

उद्घाटन के साथ ही केंद्र में प्रशिक्षण गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी गईं। प्रथम चरण में 20 ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई है। जयपुर की स्थानीय टेक्सटाइल इकाइयों ने केंद्र को कच्चे माल के रूप में कपड़ों की कटिंग एवं स्क्रीन फैब्रिक उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। पहले ही दिन फागी क्षेत्र की लगभग 60 महिलाओं ने प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया। फिनोवा कैपिटल ने भविष्य में भी महिला सशक्तीकरण की इस पहल में सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया।

उद्घाटन समारोह में जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा, प्रधान पंचायत समिति फागी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में लगभग 200 स्थानीय नागरिकों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

टॉक : शहरी सेवा शिविरों से आमजन को मिल रही त्वरित राहत, एक ही छत के नीचे 175 पट्टों का हुआ वितरण



टॉक, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में आयोजित ‘शहरी सेवा शिविर-2026’ के फॉलोअप कैप आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। टॉक नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित फॉलोअप शिविरों में नागरिकों के वर्षों से लंबित कार्यों का एक ही छत के नीचे त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। 175 पात्र लाभार्थियों को सौंपे गए पट्टे शिविर के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 175 पट्टों का वितरण लाभार्थियों को किया गया-स्टेट ग्रांट योजना: 65 पट्टे, कृषि भूमि पट्टे: 65 पट्टे, अन्य श्रेणियां: 45 पट्टे।

पट्टा प्राप्त करने वाले नागरिकों ने राज्य सरकार और प्रशासन की इस अनुत्ती पहल की सराहना करते हुए कहा कि जो काम वर्षों से अटकते हुए थे, वे अब बेहद सरल प्रक्रिया से पूरे हो रहे हैं। शिविर में नगर परिषद के साथ-साथ राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जलदाय (कांधड़), विद्युत, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई कर त्वरित समाधान किया, जिससे आमजन को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली।

भीलवाड़ा में ACB का बड़ा एक्शन : राजकीय महाविद्यालय का संस्थापन अधिकारी ?40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भीलवाड़ा। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी शिव नुवाल संस्थापन अधिकारी, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा को परिव्रादी से 40,000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिव्रादी की फर्म द्वारा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविधालय भीलवाड़ा मे आपूर्ति किये गये सिक्योरिटी गार्ड एवं कम्प्युटर ऑपरेटर एवं सफाई कर्मचारी की निविदा महाविधालय द्वारा स्वीकृत की गई। उक्त फर्म के द्वारा उक्त मानव संसाधन महाविधालय में उपलब्ध करवाये गये। आरोपी शिव नुवाल, संस्थापन अधिकारी द्वारा रबिवार को महाविधालय पहुँचने पर चौकीदार अपने कार्यस्थल महाविधालय पर उपस्थित नही होने पर प्राचार्य द्वारा संबंधित फर्म को फर्म का ठेका निरस्त करने हेतु पत्र जारी किया गया था।

खादू श्याम जी, पुष्कर और रामदेवरा का बदलेगा स्वरूप, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश

जयपुर एजेंसी। राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों के कार्याकल्प और वहां जारी विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख मंदिरों को भव्य और सुंदर रूप देकर राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। प्रमुख मंदिरों और तीर्थों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश :

पुष्कर (अजमेर) : ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग और विभिन्न घाटों का विकास कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। इसके लिए अजमेर विकास प्राधिकरण और राजस्थान धरोहर

प्राधिकरण मिलकर काम करेंगे।

खादू श्याम जी (सीकर) : मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर होगा। श्रद्धालुओं और वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए सड़क निर्माण की विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

रामदेवरा (जैसलमेर) : आगामी रामदेवरा मेले को देखते हुए पदयात्रियों के मार्गों पर पानी, विश्राम स्थल और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

बेणेश्वर धाम व तनोत माता : बेणेश्वर धाम में मूर्ति, धर्मशाला, रसोईघर और घाटों का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। वहीं तनोत माता मंदिर के प्रथम चरण का विकास कार्य तुरंत शुरू करने को कहा गया है।

डींग व पुछ्छी का लौटा : गुरु पूर्णिमा मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं



के लिए बिजली, पानी और विश्राम की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पैनोरमा का होगा संरक्षण,

स्कूली बच्चे करेंगे भ्रमण

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में बने पैनोरमा के संरक्षण पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा- ‘पैनोरमा हमारी समृद्ध और गौरवशाली विरासत का अभिन्न हिस्सा है। इनका उचित रख-रखाव

मानसून में मौसमी बीमारियों पर सख्ती, जयपुर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सौंपी जिम्मेदारी

जयपुर, एजेंसी। मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाईफस एवं अन्य वायरसजनित मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में गुरुवार को अंतरविभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर में बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने कहा कि मानसून के दौरान मच्छरों के प्रजनन एवं संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी विभाग जनजागरूकता एवं मच्छररोधी गतिविधियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मच्छरों की संक्रमण श्रृंखला को तोड़कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है। जिला कलक्टर ने पुलिस आयुक्त जयपुर व जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को मौसमी बीमारियों से संबंधित चालान कार्यवाही में सहायता प्रदान करने, घर-घर सर्वे के दौरान अग्रिय



घटनाओं को रोकने हेतु चिकित्सा विभाग की टीम का सहयोग करने तथा पुलिस थाना परिसर में मच्छर रोधी गतिविधियां करवाना सुनिश्चित करने की बात कही।

उन्होंने राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासीय कॉलोनियों एवं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में नियमित रूप से एण्टीलावा एवं सोर्स रिडक्शन गतिविधियों हेतु एण्टीमोल्डिफिकेंट एवं सुपरवाइजर को

शामिल करते हुए आईईसी गतिविधियां सुनिश्चित करें। भवन निर्माण वाले स्थान पर एंटी लावा गतिविधियां करवाई जाएं, खाली भूखण्डों में ठहरे हुए पानी में एम.पी.एस.जी. ड्रलवाएं तथा पाकों में पत्तों, कचरे एवं अन्य जल स्रोतों पर नियमित एण्टीलावा एवं सोर्स रिडक्शन गतिविधियां करवाई।

कलेक्टर ने नगर निगम को नालियों की नियमित साफ-सफाई, नालियों एवं गड्ढों में फॉगिंग, शहरी

क्षेत्र में पॉपिंग करवाने, सड़कों के आसपास बने गड्ढों को भरवाने तथा घरों के बाहर रखी टर्कियों एवं अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ ही होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव संबंधी आईईसी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला परिषद को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने, नालियां एवं जलभराव वाले स्थानों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने तथा ग्राम स्तर पर जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के माध्यम से आमजन को मलेरिया, डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए।

राइजिंग राजस्थान समित के 49 एमओयू की प्रगति की समीक्षा, मुख्य सचिव ने शीघ्र क्रियान्वयन के लिए निर्देश

जयपुर, एजेंसी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एमओयू में से चयनित 49 प्रकरणों की प्रगति की मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रत्येक मामले के शीघ्र निस्तारण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए। इनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए। इसके लिए आवश्यक नीतिगत या प्रक्रियागत निर्णय शीघ्र लिए जाएं। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) को आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित जिला कलक्टरों ने परियोजनाओं के



क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में उद्योग और व्यापार सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुधारों से निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने तथा राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए निवेश प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जा रहा है।

कोटा देहात में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: जेवीवीएनएल के जेईएन और एफआरटी कर्मचारी 1,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

कोटा, एजेंसी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कोटा देहात द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी दानमल फाल्ट रिमूवल टीम कर्मचारी व पंकज वर्मा, कनिष्ठ अभियंता, जेवीवीएनएल सुल्तानपुर जिला कोटा को आपसी मिलीभगत कर परिव्रादी के पिताजी के नाम बिजली कनेक्शन की वीसीआर नहीं भरने की एवज में परिव्रादी से 1,000 रुपये रिश्वत राशि लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा देहात को दिनांक 20.07.2026 को परिव्रादी ने एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि मेरे पिताजी के नाम पर (बिजली कनेक्शन) घर पर बिजली का मीटर लगा हुआ है। सुल्तानपुर बिजली विभाग के जे.ई.एन पंकज कुमार हमारे घर के



फोटो खिंचकर कल दिनांक 19.07.2026 को दिन में 12 बजे करीब ले गया। दानमल निवासी सुल्तानपुर बिजली विभाग के ठेके पर बिजली विभाग की गाड़ी पर तार जोड़ने का काम करता है। पंकज कुमार जे.ई.एन हमारी वीसीआर नहीं भरने के एवज में उनके दलाल दानमल निवासी सुल्तानपुर के मार्फत मेरे से 7000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। जिस पर ए.सी.बी. कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश

मीणा के सुपरविजन में ए.सी. बी. कोटा देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत के नेतृत्व में शिकायत का गोपनीय मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। दौरान गोपनीय सत्यापन परिव्रादी के रिश्वत राशि कम करने के निवेदन पर दोनों आरोपीगण ने परिव्रादी से प्राप्त कर 2,000 रुपये रिश्वत मांगकर 1000 रुपये रिश्वत राशि आरोपी दानमल ने परिव्रादी के लिए प्रित किया गया।

एसीबी कोटा देहात के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक शरीफ अहमद एवं टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दानमल एफआरटी कर्मचारी ने रिश्वत मांग के क्रम में 1000 रुपये शेष रिश्वत राशि परिव्रादी से ग्रहण करी जो राशि आरोपी दानमल से बरामद की गई। आरोपी पंकज वर्मा कनिष्ठ अभियंता की मिलीभगत पाये जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पृष्ठताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाटसएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24 ङ्ग 7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

भजनलाल शर्मा की ‘गिव अप अभियान’ पहल बनी मिसाल 1 करोड़ नए पात्र लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा कि प्रदेश में 1 करोड़ 56 हजार 511 नए जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री की अभिनव पहल के रूप में शुरू किए गए गिव अप अभियान ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और करीब 93 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छ से गरीबों के हक में खाद्य सुरक्षा छोड़ी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री का जताया आभार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर गिव अप अभियान के माध्यम से 1 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया गया गिव अप अभियान गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 नवम्बर, 2024 को ‘गिव अप अभियान’ प्रारंभ कर सक्षम लोगों को स्वेच्छ से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। करीब 3 माह बाद 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया गया ताकि वंचित पात्र लोग योजना से जुड़ सकें। पोर्टल खुलने के बाद 87 लाख 60 हजार 847 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया। इससे पहले भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12 लाख 95 हजार 664 लोगों को योजना से जोड़ा गया था।

गोदारा ने बताया कि यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है, जो गिव अप

अभियान के कारण संभव हुई है। इस अभियान में 93 लाख 48 हजार 596 सक्षम लोगों ने स्वेच्छ से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत चलाए गए गिव अप अभियान में 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्वेच्छ से सब्सिडी छोड़ी थी। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में चलाए गए इस अभियान ने प्रदेशवासियों को नया संकल दिया है। उन्होंने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ के साथ ही मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान टूर्चटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में यह उपलब्धि सशक्त राजस्थान-समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।



चपाईडांग में क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत



गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। आइकॉन क्रिकेट अकादमी के तत्वावधान में बोंदा के चपाईडांग में एक विशेष क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। आगामी 2 अगस्त को संपन्न होने वाले लड़कों के अंडर-16 वर्ग के इस 12 दिवसीय शिविर में लगभग 50 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस विशेष शिविर में मार्गदर्शन के लिए अनुभवी एवं ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षक नवाब अली के साथ-साथ एनसीए कोच संदीपान देवनाथ, पूर्व रणजी क्रिकेटर विश्वजीत मजुमदार और गौतम शर्मा प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। उन्नत खेल उपकरणों और आधुनिक तकनीकी कौशलों पर आधारित यह शिविर आइकॉन स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

राज्यपाल ने किया 47वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन



गुवाहाटी, 24 जुलाई (ख.सं.)। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज नलबाड़ी के सरिहातली स्थित नलबाड़ी स्टेडियम में 47वीं राज्य स्तरीय सोनियर और जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से चरित्र निर्माण, अनुशासन, सहनशीलता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में खेलों को अपनाने का आह्वान किया। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन असम एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा नलबाड़ी जिला प्रशासन और नलबाड़ी जिला खेल संघ के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह तीन दिवसीय करते हुए राज्यपाल ने असम भर से आये लगभग 1,200 एथलीटों की उत्साही भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की उपस्थिति राज्य में बढ़ती खेल संस्कृति को दर्शाती है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस चैंपियनशिप को ऐसे भावी चैंपियनों की पहचान करने और उन्हें तराशने का एक प्रमुख मंच बताया, जो आगे चलकर असम और देश का नाम रोशन करेंगे। राज्यपाल आचार्य ने अपने संबोधन में असम के महान खिलाड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पावन धरा ने ऐसे कई असाधारण एथलीट दिये हैं, जिन्होंने अपने निरंतर संघर्ष, अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर राज्य और राष्ट्र का मान बढ़ाया है। उन्होंने एथलेटिक्स दिग्गज भोगेश्वर बरुवा, हिमा दास, अमलान बरगोहाई और मोमिता मंडल के साथ-साथ मुक्केबाज लवलीना बरगोहाई, शिव थापा और तीर्थदाज जयंत तालुकदार का उदाहरण देते हुए कहा कि इनकी उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों को अनुशासन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने खेल भावना पर जोर देते हुए कहा कि एथलेटिक्स सहनशीलता, आत्म-अनुशासन और प्रतिबद्धता विकसित करके खेल उत्कृष्टता की नींव रखता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना, निष्पक्षता और अखंडता के सर्वोच्च मानकों को बनाये रखने का आग्रह किया। उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि पदक भले ही सफलता के प्रतीक हैं, लेकिन दृढ़ता और अनुशासन एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं। समारोह में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वजीत दैमारी, वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुवा, विधायक ऋतुपर्ण शर्मा, नलबाड़ी के जिला आयुक्त निवेदन दास पटवारी और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक बिबेकानंद दास सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।



इस मुकाबले ने यह भी दिखाया कि पीवी सिंधु का आक्रामक खेल अब भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है।

जापान ओपन में इतिहास रचने के बाद

नहीं लांघ पाई 'चीनी दीवार'

टोक्यो(एजेंसी)। जापान ओपन सुपर 1000 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चाइना ओपन में अपना विजयी अभियान जारी नहीं रख पाईं। दूसरे दौर में उन्हें मेजबान चीन की चेन युफेई के खिलाफ 21-16, 20-22, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु दूसरे गेम में चार मैच पॉइंट भी नहीं भुना पाईं। इसके बाद युफेई ने शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का चाइना ओपन सुपर 1000 में सफर दूसरे दौर में ही समाप्त हो गया। **शानदार शुरुआत, पहले गेम में की दमदार वापसी-** पीवी सिंधु के लिए मुकाबले की शुरुआत आसान नहीं रही। वह पहले गेम में 6-12 से पीछे चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि चेन युफेई आसानी से बढ़त बना लेंगी, लेकिन कोच इस्वांश्या के मार्गदर्शन के बाद पीवी सिंधु ने अपनी रणनीति बदली और लगातार क्रॉस-कोर्ट शॉट्स से चीनी खिलाड़ी को कोर्ट के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ाया।

- दूसरे गेम में 4 मैच पॉइंट भी नहीं दिला सके जीत-** दूसरे गेम में भी पीवी सिंधु पूरे समय हावी रही। उन्होंने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और एक समय स्कोर 20-16 कर लिया। यानी उनके पास मुकाबला खत्म करने के लिए चार मैच पॉइंट थे, लेकिन यहीं से मैच का रुख बदल गया। ओलंपिक चैंपियन रह चुकीं चेन युफेई ने जबरदस्त वेर्य दिखाया और लगातार छह अंक जीतकर गेम 22-20 से नाम कर लिया। इस दौरान पीवी सिंधु ने कुछ जल्दबाजी भरे फैसले किये और दो बार शटल को बाहर समझकर छोड़ दिया, लेकिन वह लाइन के अंदर गिरी।
- निर्णायक गेम में 15-13 की बढ़त भी नहीं बचा सकी-** निर्णायक गेम में भी पीवी सिंधु ने हार नहीं मानी। पीवी सिंधु ने 15-13 तक बढ़त बना ली थी और जीत की

ओर बढ़ती दिख रही थी। हालांकि, लगातार सातवां मैच खेल रही पीवी सिंधु पर थकान साफ दिखाई देने लगी। पीवी सिंधु के रमेश में पहले जैसी ताकत नहीं रही और कई आक्रमण नेट में फंस गए। दूसरी ओर, घरेलू दर्शकों के समर्थन से खेल रही चेन युफेई ने आत्मविश्वास के साथ वापसी की और लगातार अंक जुटाते हुए तीसरा गेम 21-18 से जीत लिया। **●सुधार की जरूरत भी आई सामने-** इस मुकाबले ने यह भी दिखाया कि पीवी सिंधु का आक्रामक खेल अब भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। हालांकि, मैच खत्म करने के अहम मौकों पर संयम बनाए रखना उनके लिए अभी बड़ी चुनौती है। चार मैच पॉइंट हासिल करने के बाद मिली यह हार पीवी सिंधु के लिए निराशाजनक जरूर रही, लेकिन जापान ओपन के

थकान भी बनी हार की बड़ी वजह

पिछले सप्ताह जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद यह पीवी सिंधु का 10 दिनों में सातवां मुकाबला था। पुरे मैच में पीवी सिंधु ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन निर्णायक क्षणों में थकान उनके खेल पर हावी होती दिखी। लंबे रैलियों के दौरान उनकी गति और रमेश की ताकत दोनों प्रभावित हुईं। चीनी शटलर युफेई ने इसका पूरा फायदा उठाया।

खिताब और चाइना ओपन में चेन युफेई जैसी मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने यह संकेत भी दिया कि वह फिर अपनी सर्वश्रेष्ठ लय की ओर लौट रही हैं।

भारत ने जीता पहला टी20, वैभव नहीं मयंक बने मैच के हीरो

अख्यर की कप्तानी में पहली जीत

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने श्रेयस अख्यर की कप्तानी में पहले सात में से छह मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज कर ली है। जिम्बाब्वे दौर पर टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है। तीन मैचों की टी20 सीरीज में इसी के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त भी बना ली है। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 18 गेंद पर अर्धशतक जड़ा और जमकर महफ़िल लुटी। मगर वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद की पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए। मगर 21 महीने बाद भारतीय टीम में लौटे मयंक यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी से सबका दिल जीता। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयस अख्यर की भी बतौर कप्तान यह पहली टी20 इंटरनेशनल जीत है। यह भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में बिना जीत के लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने का अनचाहा रिकॉर्ड भी है। साथ ही टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल में 120 प्लस का लक्ष्य चेज करते हुए सबसे ज्यादा गेंद बची रहने के लिहाज से चौथा सर्वश्रेष्ठ रन चेज है। वहीं श्रेयस अख्यर ने लगातार आठ टी20 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतते हुए भी खास रिकॉर्ड बनाया।

भारत की 7 विकेट से शानदार जीत

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच हराये में खेला गया। भारत ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर ही 126 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अख्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे। वेस्ली मधेवेरे 39 और मरुमानी ने 27 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को 2-2 विकेट मिले। जबकि रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। बल्लेबाजी में वैभव के 50 रन के अलावा इशान किशन ने 35 रन बनाए और कप्तान श्रेयस अख्यर 28 रन बनाकर नाबाद रहे।



120+ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सबसे बड़ी जीत (बची हुई गेंद के लिहाज से)

- 60 गेंद बाकी : बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 2026 (लक्ष्य : 154)
- 49 गेंद बाकी : बनाम बांग्लादेश, ग्वालियर, 2024 (लक्ष्य : 128)
- 43 गेंद बाकी : बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 2025 (लक्ष्य : 133)
- 40 गेंद बाकी : बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2026 (लक्ष्य : 126)

जिम्बाब्वे के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम पर हनुमा विहारी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। हनुमा विहारी ने जिम्बाब्वे दौर पर 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में रजत पाटीदार को बाहर रखने के लिए टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की आलोचना की है। विहारी का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन और खिताबज जिताने के बाद पाटीदार को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। विहारी ने टीम के ओवरऑल बैलेंस पर भी सवाल उठाए। विहारी ने कहा कि चयनकर्ताओं ने कुछ मुश्किल फैसले लिए खासकर रजत पाटीदार को बाहर रखकर। हालांकि, टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्हें लगा कि पाटीदार या संजु सैमसन जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाजों से टीम को बेहतर बैलेंस मिलता। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रिंकू सिंह को वापस लाया गया, लेकिन रजत पाटीदार कहां हैं? उन्होंने आरसीबी को दो सीजन में खिताब जिताया और बल्लेबाज के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें भी नहीं चुना गया। ये चयनकर्ताओं के कड़े फैसले हैं।'



मयंक यादव वापसी करते ही बने प्लेयर ऑफ द मैच

नई दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव का करियर काफी मुश्किल भरा रहा है। 24 साल का यह युवा खिलाड़ी चोट की वजह से दो साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहा। तेज रफ्तार से गेंद करने के कारण 'राजधानी एक्सप्रेस' नाम से मशहूर दिल्ली के लड़के ने जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार (23 जुलाई) को दमदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बना।

अक्टूबर 2024 के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए मयंक यादव ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ही गेंद पर विकेट लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक ने माना कि 22-23 साल की उम्र में बार-बार चोटिल होना मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी की। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने के सपने के कारण मुश्किल रिहैबिलिटेशन पीरियड के दौरान उनका हौसला नहीं टूटा।

CJP प्रदर्शन और छात्रों के मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर का बयान, शुभमन गिल ने भी कही यह बात

नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक़्त कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले ने 20 जुलाई 2026 को तूल पकड़ा जब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। अब इस मामले पर बॉलीवुड से खेल जगत तक अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी प्रतिक्रिया दी है।

सचिन तेंदुलकर ने छात्रों का समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और यह भी याद दिलाया कि उनके पिता भी एक प्रोफेसर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का अहम योगदान होने वाला है। इसलिए सभी को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। किसी भी परीक्षा में फेल हो जाएं लेकिन नकल करना सही नहीं है।



‘मेरे पिता भी प्रोफेसर थे...’

सचिन तेंदुलकर का पूरा बयान?

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक नोट पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे पिता भी एक प्रोफेसर थे। वे कई युवा छात्रों के मार्गदर्शक और गुरु थे। एक सबक जो उन्होंने मुझे शुरुआत में ही सिखाया था, असफल होना ठीक है, लेकिन नकल (चीटिंग) करना नहीं। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। समाज के एक बड़े और जिम्मेदार होने के नाते, कल्चर को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जो समाज प्रयास से ज्यादा परिणामों को प्राथमिकता देता है, वह योग्यता (मेरिटोक्रेसी) की जगह शॉर्टकट को तलाशने लगता है।' मास्टर ब्लास्टर ने आगे लिखा, 'आज, जब छात्र इस बात से निराश महसूस करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला है, तो यह स्वाभाविक है। सामूहिक रूप से, हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि वे दोबारा कभी ऐसा महसूस न करें। युवा भारत सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ है। वे (छात्र और युवा) हमारी सफलता का ईंधन हैं। अंत में सचिन ने पोस्ट में लिखा, 'एक समाज के रूप में, हम सभी, माता-पिता, शिक्षक, मित्र, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासक, की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे युवा प्रोत्साहित और ऊर्जावान रहें।' 'हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहाँ कड़ी मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता की जीत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ऐसे समाधान ढूँढ लेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करेंगे।'



स्कोडा ने स्लाविया मॉटे कार्लों के कलर पैलेट का किया विस्तार

गुवाहाटी, 24 जुलाई। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी स्लाविया रेंज का विस्तार करते हुए स्लाविया मॉटे कार्लों के लिए दो नये विशेष रंग विकल्प शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे पेश किए हैं। ये दोनों रंग आकर्षक ड्यूल-टोन फिनिश में उपलब्ध हैं। केवल 200 यूनिट तक सीमित, स्लाविया मॉटे कार्लों के ये विशेष रंग संस्करण सेडान के गतिशील डिजाइन, रोमांचक ड्राइविंग अनुभव और ब्रांड की रेली मॉटे कार्लों विरासत का शानदार संयोजन प्रस्तुत करते हैं। यह नया विस्तार कार को और भी प्रभावशाली दृश्य पहचान प्रदान करता है तथा उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो अधिक विशिष्ट और प्रीमियम स्वामित्व अनुभव की तलाश में हैं। इस लॉच पर टिप्पणी करते हुए स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि स्लाविया मॉटे कार्लों को उसके विशिष्ट डिजाइन, प्रीमियम आकर्षण, रोमांचक ड्राइविंग डायनेमिक्स और हमारी मोटरस्पोर्ट विरासत से मजबूत जुड़ाव के लिए ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। हम मॉटे कार्लों रेंज की विशिष्ट पहचान और आकर्षण को और अधिक सशक्त बना रहे हैं, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प और विशिष्टता मिल सके। स्लाविया मॉटे कार्लों लगातार स्टाइल, प्रदर्शन और आधुनिकता का बेहतरीन संगम प्रस्तुत करती है। हम अपने ग्राहकों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप अपने सेडान पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना जारी रखेंगे। सीमित संस्करण मॉटे कार्लों नये विशेष रंग विकल्पों के अलावा, स्लाविया मॉटे कार्लों अपनी ब्लैकड-आउट एक्सटीरियर डिजाइन, विशिष्ट मॉटे कार्लों स्टाइलिंग तत्वों, प्रीमियम ब्लैक और रेड इंटीरियर थीम तथा फीचर-समृद्ध कैबिन के साथ अपनी अलग पहचान बनाये रखती है। नये शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे ड्यूल-टोन फिनिश स्लाविया रेंज के सबसे आकर्षक वैरिएंट्स में से एक की तलाश कर रहे ग्राहकों को और अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।

पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसर को दिया जा रहा है बढ़ावा

गुवाहाटी, 24 जुलाई। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में गुणवत्तापूर्ण अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं की रोजगार क्षमता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कീम (पीएम-नैप्स) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल के विस्तार की शुरुआत की है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई) गुवाहाटी द्वारा लागू किया जाएगा। मई 2025 में शुरू की गयी पायलट पहल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस विस्तारित पहल का उद्देश्य सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में अप्रेंटिसशिप की पहुंच को बढ़ाना, इंस्टीट्यूट और सरकारी संस्थानों की भागीदारी को बेहतर बनाना और स्किल इंडिया मिशन के तहत इस क्षेत्र के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के लिए पाथवे का निर्माण करना है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पहल का दायरा बढ़ाया है और 30,000 अप्रेंटिस का नया लक्ष्य तय किया है, जो पायलट चरण की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत ज्यादा है। इनमें से, 15,000 अप्रेंटिस को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर, जिसमें सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) शामिल हैं, जिसमें अवसरों के लिए मदद दी जाएगी, जबकि अन्य 15,000 अप्रेंटिस को इसी क्षेत्र में यानी उनके अपने राज्यों में काम पर रखा जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, इस पहल के लिए 57.58 करोड़ रुपये की राशि तय की है। यह राशि पीएम-नैप्स के पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य कंपोनेंट से उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यहाँ के युवा, टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी आबादी देश की विकास यात्रा में योगदान देने के लिए तैयार है। इस पायलट पहल की शानदार सफलता यह दिखाती है कि सही अवसरों और सहयोग से, हमारे युवा अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम-नैप्स के तहत इस पहल को आगे बढ़ाकर, हम गुणवत्तापूर्ण अप्रेंटिसशिप अवसरों तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। लोकल इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं और इस क्षेत्र के युवाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूरे देश में काम की जगह पर कीमती अनुभव हासिल करने में सक्षम बना रहे हैं।

सफलता की चाबी दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहने में है, सच्चा लीडर चुनौतियों को अवसरों में बदल देता है'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अपनी कारोबारी सफलता के साथ-साथ अपने दूरदर्शी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। लगभग 2.1 अरब डॉलर की संपत्ति वाले आनंद महिंद्रा 22 प्रमुख उद्योगों में फैले कारोबारी साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2020 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' से नवाजा गया था। सोशल मीडिया पर अवसर प्रेरणादायक कहानियां और टैलेंट की तारीफ करने वाले महिंद्रा ने सफलता, इनोवेशन और लीडरशिप पर कई ऐसे सबक दिए हैं, जो हर व्यक्ति और युवा उद्यमी के काम आ सकते हैं। यहां आनंद महिंद्रा के बिजनेस से जुड़े 10 अनमोल विचार दिए गए हैं।

दुनिया कैसे बदलेगी, यह कोई नहीं समझ सकता। भविष्य की योजना बनाने का एकमात्र तरीका अलग-अलग परिस्थितियों की कल्पना करना है और फिर उनमें से किसी एक पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाना है। कभी-कभी इनोवेशन तभी संभव हो पाता है जब आपके

महंगे तेल ने बिगाड़ा खेल! दो दिन में 4,400 फिसला सोना, चांदी 9,600 सस्ती



नई दिल्ली, एजेंसी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि पश्चिम एशिया में संकट गहराने के कार ब्रेंट क्रूड की कीमत एक बार फिर 100 प्रति बैरल के पार चली गई है। इससे महंगाई की चिंता बढ़ गई है और निवेशकों को आशंका है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। इसका असर सोने और चांदी की कीमत पर देखने को मिल रहा है।

एमसीएक्स पर सितंबर 2026 डिलीवरी

सोने और चांदी की इंटरनेशनल कीमतें

इस बीच स्पॉट गोल्ड 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,042.77 प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले बुधवार को यह दो हफ्ते के हाई पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद इसमें 120 से ज्यादा गिरावट आई है। अगस्त डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,045.60 पर आ गया। हालांकि यह अब भी 0.6 प्रतिशत की मामूली साप्ताहिक बढ़त की राह पर है। इसी तरह स्पॉट सिल्वर 0.2 प्रतिशत गिरकर 57.56 प्रति औंस पर आ गई। रेजिस्टेंस 1,43,500-1,44,400 रुपये है। इसी तरह चांदी के लिए सुपोर्ट 2,16,000-2,14,000 रुपये और रेजिस्टेंस 2,22,000-2,24,400 रुपये है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स बाजार में गिरावट के दौरान सोना और चांदी खरीद सकते हैं लेकिन ट्रेंडर्स को अगले हफ्ते होने वाली स्महस्थ मीटिंग से पहले लॉन्ग पोजीशन लेने से बचना चाहिए।

होर्मुज के बाद अब ‘रेड सी’ में बवाल 100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल

नई दिल्ली, एजेंसी। होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब लाल सागर में बवाल पैदा हो गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। ऐसे में दुनिया में फिर से तेल संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। इसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है।

दरअसल, लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दो सऊदी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भीषण आग लग गई है। गुरुवार को लेंट ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 100 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया, जो पिछले आठ हफ्तों में इसका उच्चतम स्तर है। वहीं अमेरिकी क्रूड भी लगातार दूसरे सत्र में 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो 11 जून के बाद का सबसे ऊपरी स्तर है।

अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करने वाले भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों



अब ‘रेड सी’ में नया मोर्चा

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर (रेड सी) में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमलों का दावा किया है। इससे पहले हूतियों ने सऊदी साम्राज्य पर नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की थी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से जहाजों पर ज्यादातर हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास केंद्रित थे। हालांकि, हम हमलों से साफ है कि अब खतरा लाल सागर तक फैल गया है, जो वैश्विक तेल बाजार के लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन गया है।

में उछाल से भारतीय तेल विपणन कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ेगा। अगर क्रूड 100 डॉलर के ऊपर बना रहता है, तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का दबाव बनेगा। इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा, जिससे सब्जी, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।

लाल सागर का रास्ता कितना अहम

लाल सागर यानी रेड सी का रास्ता बेहद अहम है क्योंकि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से होकर प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है। इसके अलावा, दुनिया का 12 से 15 फीसदी समुद्री व्यापार (1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य) इसी जलमार्ग से गुजरता है।

1 महीने में 35 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ क्रूड

होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही पहले ही नाममात्र रह गई है, जिससे लाल सागर का रास्ता बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अब इस रुत पर भी संकट मंडराने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से उछली हैं। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में

तमिलनाडु को केंद्र से कम मिला पैसा फिर भी भर गया सरकारी खजाना

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय उर्फ थलपति विजय को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) में अच्छी खबर मिली है। पहली तिमाही में तमिलनाडु सरकार की कुल कमाई (राजस्व) में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केग) के शुरूआती आंकड़ों के



मुताबिक, यह बढ़त राज्य के अपने बेहतर टैक्स कलेक्शन की वजह से हुई है, जिसने केंद्र सरकार से मिले कम फंड की भरपाई कर दी। जून 2026 के बीच कुल 64,944.97 करोड़ रुपये की कमाई हुई। वहीं, पिछले साल इसी दौरान राज्य को 63,755.70 करोड़ रुपये मिले थे। यानी इस साल तमिलनाडु की कमाई में 1,189.27 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते कर्ज से जूझ रही थलपति विजय सरकार के लिए यह राहत भरी खबर है। तमिलनाडु की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उसके अपने टैक्स कलेक्शन से आया। पिछले साल यह रकम 56,366.76 करोड़ रुपये थी। कमाई के मुख्य स्रोत में स्टेट जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला सेल्स टैक्स, शराब पर एक्ससाइज ड्यूटी और गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्स आदि रहा।

केंद्र से मिलने वाला फंड घटा

राज्य ने टैक्स कलेक्शन में तो बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में भारी कमी दर्ज की गई। अप्रैल-जून 2026 के दौरान तमिलनाडु को केंद्र से सिर्फ 1,710 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 4,493.23 करोड़ रुपये थी। केंद्र से मिलने वाली सहायता में 2,783 करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट आई। इससे राज्य को टैक्स से हुए ज्यादा फायदे का असर थोड़ा कम हो गया। कैग की रिपोर्ट से साफ है कि तमिलनाडु अब अपने खर्चों और सरकारी खजाने को चलााने के लिए केंद्र के फंड पर निर्भर रहने के बजाय खुद के टैक्स कलेक्शन और कमाई के स्रोतों पर ज्यादा मजबूत हो रहा है। बेहतर टैक्स कलेक्शन से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी इस तिमाही की सबसे बड़ी चुनौती रही।

हूती हमले से क्रूड ऑयल में खलबली...100 डॉलर के पार, भारत की बढ़ सकती है टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में खलबली मच गई है। एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू होने लगी हैं। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 6 प्रतिशत से अधिक उछलकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो पिछले आठ सप्ताह का सबसे उंचा स्तर है।

वहीं, अमेरिकी क्रूड में भी लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इस दौरान यह 5 प्रतिशत से



ज्यादा बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। यह 11 जून के बाद सबसे ज्यादा है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस तेजी का असर भारत पर भी पड़ने की आशंका है। बता दें कि भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो कच्चे तेल के आयात का बिल बढ़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ने की आशंका रहेगी।

ताजा दावों से पता चलता है कि यह खतरा अब लाल सागर तक फैल सकता है,

जिससे तेल बाजार के लिए एक और चिंता का विषय बन गया है। लाल सागर का रास्ता इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में जाने वाला लाखों बैरल तेल बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इस जलमार्ग से दुनिया का लगभग 12-15 प्रतिशत समुद्री व्यापार भी होता है, जिसकी कीमत सालाना 1 ट्रिलियन से अधिक है। होर्मुज जलडमरूमध्य से बाधा के बीच इसे एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है।

9000 की नौकरी छोड़ बेसमेंट से शुरू किया काम 8 करोड़ का साम्राज्य, जेएसडब्ल्यू और एचसीएल जैसी कंपनियां भी ग्राहक

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आपके पास हैसला और सही सोच है, तो छोटे से कदम से भी बड़ी शुरुआत हो सकती है। कोयंबटूर के रहने वाले 34 साल के शशि धरन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। साल 2020 में अपने घर के 1000 स्क्वायर फीट के छोटे से बेसमेंट से शुरुआत करने वाले शशि की कंपनी कोवई कियोस्क आज 8 करोड़ रुपये का टर्नओवर बना चुकी है। यह कंपनी खाने-पीने के छोटे स्टॉल (कियोस्क), बड़े कर्मशियल ड्रावे, किचन के सामान और आधुनिक 'केप्सूल हाउस' बनाती है। शशि धरन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 'द वीकेंड लीडर' के मुताबिक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 9000 रुपये की नौकरी से की थी। धीरे-धीरे अनुभव हासिल करते हुए उनकी सैलरी 60,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन वे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। शशि ने 2

लाख रुपये अपनी बचत से लगाए और 4 लाख रुपये सरकार की योजना से लोन लिया। शुरुआत के



कई बड़ी कंपनियां क्वाइट: आज कंपनी की कमाई में 60 प्रतिशत हिस्सा कियोस्क से, 20

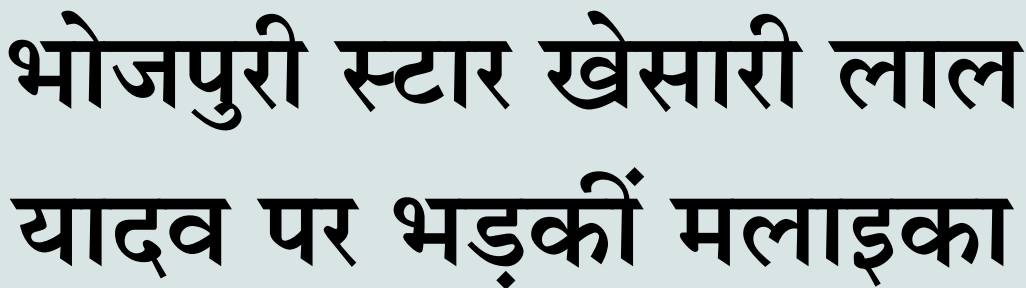
एक छोटे ऑर्डर ने बदल दी पूरी किस्मत

शुरुआत में शशि सिर्फ रेस्टोरेंट और होटलों के लिए किचन इक्विपमेंट बनाते थे। लेकिन 2022 में एक कस्टमर ने उनसे 1.8 लाख रुपये का फिश फ्राई स्टॉल (कियोस्क) बनाने को कहा। यह प्रोडक्ट लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें ऐसे कई ऑर्डर मिलने लगे। हाल ही में उनकी कंपनी ने 60 लाख रुपये का एक बहुत बड़ा कियोस्क प्रोजेक्ट पूरा किया है।

2 से 100 कर्मचारियों का सफर

जिस कंपनी में शुरुआत में सिर्फ 2 लोग काम करते थे, आज वहां 100 लोग काम कर रहे हैं। घर के बेसमेंट से शुरु हुआ काम आज 80,000 स्क्वायर फीट की बड़ी फैक्ट्री में बदल चुका है।

प्रतिशत किचन के सामान से और 20 प्रतिशत केप्सूल हाउस से आता है। स्टील और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां भी इनकी क्वाइट हैं। शशि धरन का मानना है कि बिजनेस में रातों-रात सफलता नहीं मिलती। वे नए उद्यमियों को सलाह देते हैं कि हर नए बिजनेसमें को शुरुआत के 5-6 सालों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।



मलाइका का कमेंट सामने आने के बाद कई लोग खेसारी लाल यादव की पैरवी करते हुए उनकी पहचान बता रहे हैं। वहीं कुछ ट्रोल्स ऐसे भी हैं, जो मलाइका को ही ट्रोल् कर रहे हैं। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म *साजन चले ससुराल* (2011) सुपरहिट रही, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया।

An ISO 9001 : 2015 Certified Co.

POWER 7 TUBULAR BATTERY

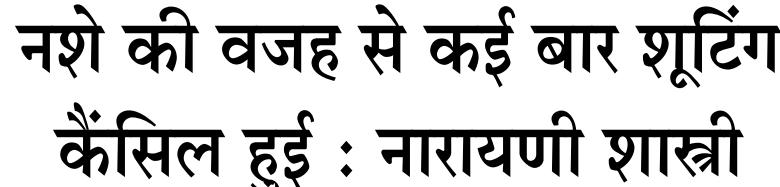
Your home, always powered with Power 7 Tubular Battery

**36
Months
Warranty**

For More Information - Helpline No. : +91 8011114754

E : skind7@rediffmail.com, advtski@gmail.com, w: www.power7battery.com, You tube : power7battery

संजू : तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जमा त
मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना।



है। हमारी शूट कैसिल हुई है, क्योंकि एक्टर्स शूट करने की हाजत में नहीं है। मगरो एक्टर्स सेट पर बैठे हैं, लेकिन शूट नहीं हो रही, क्योंकि लोग छुट्टा हो लयक नहीं हैं। मेरे आखिरी दो शोज में ऐसा न हुआ है, लेकिन पिछले शोज में ये बहुत हुआ है। अपने विवादित बयान में नारायणी शास्त्री साफ किया है कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं हैं, उन्होंने सारे नो सिर्फ ट्राय करके के लिए इस्तेमाल किया है। एक्ट्रेस ने सफाई में कहा है कि उन्होंने पहली बार शोब ड्रग्स लिए, जिससे उन्हें पता रहे कि अगर कोई स्टार ड्रग्स लेता है तो पता हो कि उसका पता कैसे है।

प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही कई अन्य नए सरस्वती में भी आजीवन सदस्यता ग्रहण की। शाखा के सचिव ने नए सरस्वती से अपील करते हुए कहा कि वे शाखा की वर्तमान बजटाकर 2005 संख्या को 150 से बढ़ाकर 200 संख्या तक शाखा की शक्ति को और बढ़ावा मिले। उन्होंने बताया कि आगामी असम साहित्य रूपा में केंद्रीय बाल दिवस कार्यक्रम सभा का शाखा साहित्य सभा की मेजबानी में रूपाई में ही आयोजित किया जाएगा, और शाखा की पहल पर 50 पुस्तकें प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है। इस कार्य के लिए उन्होंने जनता का आशीर्वाद मांगा। सभा की उद्देश्य व्याख्या रूपाई शततल शाखा साहित्य सभा के सचिव रातुल गोगोई ने की और धन्यवाद शान्न द्युता-संसद उप-समिति के संयोजक वीरल सोनोवाल ने किया। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसकी जानकारी शाखा साहित्य सभा के सचिव रातुल गोगोई ने दी है।

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में 70 से अधिक गुप्त नवरात्र में श्री राम कथा के आवारा कुत्तों का एंटी रेबीज टीकाकरण आयोजन से शक्ति का संचार

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 24 जुलाई। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया गया। एनिमल वेलफेयर पीपुल (एडब्ल्यूपी), डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ पशु चिकित्सा विभाग (बरबरूवा ब्लॉक) तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के लिटिल फ्रेंड्स ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले 70 से अधिक आवारा कुत्तों का सफलतापूर्वक एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। अभियान का उद्देश्य परिसर में रहने वाले पशुओं को रेबीज से सुरक्षित रखना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना था। इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसे एनिमल वेलफेयर पीपुल (एडब्ल्यूपी) के सहयोग से आयोजित किया गया। इस संस्था की स्थापना



डिब्रूगढ़ में ‘डॉस फादर’ के नाम से विख्यात स्वर्गीय विनीत बगड़िया ने वर्ष 2018 में की थी। पशुओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समर्पण ने

डिब्रूगढ़ में पशु कल्याण की एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में सैकड़ों घायल, बीमार और बेसहारा कुत्तों तथा अन्य पशुओं

का उपचार, बचाव और पुनर्वास कराया तथा लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए लगातार प्रेरित किया। विनीत बगड़िया के निधन के बाद भी उनकी स्थापित संस्था एनिमल वेलफेयर पीपुल उसी समर्पण के साथ पशु संरक्षण और जनजागरूकता का कार्य कर रही है। शहर में घायल पशुओं के उपचार, एंटी रेबीज टीकाकरण, भोजन उपलब्ध कराने, रेस्क्यू अभियान चलाने तथा पशु कूरता के मामलों में हस्तक्षेप करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से संस्था लगातार समाज सेवा में जुटी हुई है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित यह टीकाकरण अभियान भी उसी मानवीय सोच और सेवा भावना का विस्तार माना जा रहा है। अभियान के दौरान पशु चिकित्सा विभाग की टीम और स्वयंसेवकों ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर में घूमकर चिन्हित आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया। स्वयंसेवकों ने कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने, उन्हें नियंत्रित करने और टीकाकरण के बाद पुनः उनके प्राकृतिक वातावरण में

छोड़ने की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया। अभियान में विश्वविद्यालय के लिटिल फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्यों ने भी सक्रिय सहयोग दिया।विश्वविद्यालय समुदाय तथा स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान केवल पशुओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लोगों ने कहा कि स्वर्गीय विनीत बगड़िया द्वारा शुरू किया गया पशु सेवा का मिशन आज भी समाज को प्रेरित कर रहा है, और एनिमल वेलफेयर पीपुल उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए डिब्रूगढ़ में पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी डिब्रूगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के एंटी रेबीज टीकाकरण एवं पशु कल्याण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि पशुओं और मनुष्यों के बीच सुरक्षित एवं संवेदनशील सह-अस्तित्व को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

जय श्री राम जय श्री कृष्ण सेवा समिति का धार्मिक यात्रा आज **लखीमपुर, 25 जुलाई (ख.सं।)** बीआरबीएनएमपीएल टाउनशिप स्थित जय श्री राम जय श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा आगामी श्रावण मास के उपलक्ष्य पे दो दिवसीय धार्मिक भ्रमण यात्रा श्री धाम मायापुर (इस्कॉन) के लिए रवाना। समिति के अध्यक्ष श्री बी. सी. मंडल एवं सचिव श्री शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि यह यात्रा 25 जुलाई शनिवार को प्रस्थान करेगी तथा 26 जुलाई रविवार को वापस लौटेगी। यात्रा में समिति के लगभग 70 सदस्य श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भक्तों को भगवान के धाम के दर्शन कारकर आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना है। यात्रा के दौरान नाम संकीर्तन, सत्संग, भजन-कीर्तन एवं सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाएगा। समिति का मुख्य उद्देश्य बीआरबीएनएमपीएल टाउनशिप में शांति,सद्भाव,भाईचारा एवं मानव कल्याण के लिए पूजा पाठ के अलावे धार्मिक एवं साम्प्रुतिक कार्यक्रमों में मौके पे भंडारे के आयोजन से भूखे लोगों को खाना खिलाना शामिल है।

डिब्रूगढ़ बना राहत अभियान का केंद्र, आसू ने शहरवासियों के सहयोग से चराइदेव और शिवसागर के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी बड़ी राहत खेप

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 24 जुलाई। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच डिब्रूगढ़ एक बार फिर सामाजिक एकजुटता और मानव सेवा का केंद्र बनकर उभरा है। आल डिब्रूगढ़ जिला छात्र संघ (आसू) ने शहरवासियों के सहयोग से एकत्रित बड़ी मात्रा में राहत सामग्री शुक्रवार को चराइदेव और शिवसागर जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रवाना की। राहत दल आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल, कपड़े, स्वच्छता संबंधी सामग्री तथा अन्य जरूरी सामान लेकर प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ, जहां इन्हें सीधे जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। इस मानवीय पहल की शुरुआत डिब्रूगढ़ के चौकीडिंगी स्थित शहीद भवन से हुई, जहां आसू ने लगातार दो दिनों तक राहत सामग्री संग्रह अभियान चलाया। इस अभियान में डिब्रूगढ़ के नागरिकों, व्यापारियों, सामाजिक

संगठनों, छात्र-छात्राओं, युवाओं तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। लोगों ने स्वेच्छा से चावल, दाल, चिउड़ा, बिस्कुट, पेयजल, कपड़े, बच्चों के उपयोग की सामग्री, स्वच्छता उत्पाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। आसू के पदाधिकारियों ने बताया कि डिब्रूगढ़ से भेजी गई राहत सामग्री को संगठन के प्रशिक्षित स्वयंसेवक चराइदेव और शिवसागर के उन गांवों और राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे, जहां बाढ़ ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। राहत सामग्री का वितरण स्थानीय इकाइयों के समन्वय से सीधे प्रभावित परिवारों के बीच किया जाएगा, ताकि सहायता बिना किसी बाधा के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके। संगठन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय डिब्रूगढ़ के लोगों ने जिस एकजुटता,

सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना का परिचय दिया है, वह पूरे असम के लिए प्रेरणादायक है। बड़ी संख्या में लोगों ने राहत सामग्री देकर यह साबित किया है कि संकट की घड़ी में डिब्रूगढ़ हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहता है। आसू ने राहत अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले प्रत्येक नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवक के प्रति आभार व्यक्त किया।आसू ने बताया कि यदि बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती है या प्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त सहायता की मांग आती है, तो डिब्रूगढ़ में राहत सामग्री संग्रह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। संगठन ने आम जनता से इस मानवीय अभियान में निरंतर सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि समाज के सामूहिक प्रयासों से ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत और संबल मिल सकेगा।

संवाददाता

मोरानहाट, 24 जुलाई। असम में सड़क संपर्क को अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्यसभा सांसद योगेन मोहन ने कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मोरान पोलो मैदान से तिलैनगर (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-37) तक सड़क के विस्तार तथा इसे फोरलेन मार्ग में विकसित करने की मांग को लेकर एक विस्तृत जापन सौंपा। बैठक के दौरान सांसद योगेन मोहन ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष इस सड़क की वर्तमान स्थिति, क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव



तथा भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोरान पोलो मैदान से तिलैनगर

तक का मार्ग स्थानीय लोगों, व्यापारिक गतिविधियों और क्षेत्रीय आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सड़क

का चौड़ीकरण और इसे चार लेन में विकसित किया जाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जापन में कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुगम होगी, बल्कि यात्रा समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे असम के समग्र विकास को गति मिलेगी। राज्यसभा सांसद योगेन मोहन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सकारारत्मक सहयोग पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार

इस महत्वपूर्ण मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि माननीय गडकरी के सहयोग से असम की परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलेगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार देशभर में सड़क अवसंरचना के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। ऐसे में मोरान पोलो मैदान से तिलैनगर (पुराना एनएच-37) तक सड़क को फोरलेन में विकसित करने की यह मांग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

तेजपुर में श्री मारवाड़ी दुर्गा पूजा समिति की हुई बैठक



तेजपुर, 24 जुलाई (ख.सं।) श्री मारवाड़ी दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक श्री मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला प्रांगण में आयोजित की गयी। समिति के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीनदयाल आसोपा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक मे प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाने के

लिए कई विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक मे सचिव जीतू बोर्ड, पूर्व अध्यक्ष प्रेम झंवर, पूर्व सचिव बिष्णु डागा, पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण बाहेती, सलाहकार रामरतन पांड्या, के अलावा राजशर्मा, आनंद शर्मा, जुगल पांड्या, प्रमोद बगड़ा, जीतेंद्र लढा, कामछया पारीक, राजेश अग्रवाल आदि शामिल थे।

श्रद्धा व उल्लास के साथ निकाली गयी भगवान जगन्नाथ की उल्टी रथ यात्रा

कोकराझाड़, 24 जुलाई (ख.सं।) कोकराझाड़ जिले के फकीराग्राम में आज भगवान जगन्नाथ की घर वापसी (बहुड़ा) रथ यात्रा पूरी श्रद्धा, उद्गस और भव्यता के साथ संपन्न हुई।

फकीराग्राम के रेलवे कॉलोनी स्थित लोकनाथ बाबा मंदिर से रथ आयोजक समिति के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर चार बजे शुरू हुई इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा और हर कोई भक्ति रस में सराबोर नजर आया। इस दौरान भक्तों में रथ की पवित्र रस्सी को खींचने के लिए होड़ मची रही। लोगों की अटूट मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर



हो जाते हैं। रथ यात्रा का मार्ग फकीराग्राम बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए यह रथ यात्रा अपने निर्धारित पड़ाव से गुजरी। यात्रा सबसे पहले राधा-गोबिंदो मंदिर पहुंची, वहां से पुराणबाजार दुर्गा मंदिर होते हुए अंत में कुमारगंज में जाकर पूरी हुई। इस पावन अवसर पर स्थानीय निवासियों ने सेवा भाव का अनुदा उदाहरण पेश किया। चिलचिलती और

भीषण गर्मी के बीच यात्रा मार्ग पर जगह-जगह भक्तों के लिए शीतल जल, शरबत और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गयी थी, जिसकी सभी ने भूर्र-भरि प्रशंसा की। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम रथ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी,



ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की एक झलक पा सकें और उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके।

सिलचर से हमारे संवाददाता के अनुसार भक्तिमय वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज द्वारा आज सिलचर में उल्टा रथ यात्रा या बहुदा यात्रा का आयोजन किया गया।

रंगिरखारी से शुरू हुआ यह सुशोभित रथ शहर की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों से होते हुए अंबिकापत्ती स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचा। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक, बहुदा यात्रा, रथ यात्रा के नौ दिन बाद मनायी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर से अपने मंदिरों में

लौटते हैं। यह वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के औपचारिक समापन का प्रतीक है। दूसरी ओर रथ यात्रा के अवसर पर रंगिरखारी से शुरू हुई शोभायात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा इलाका हरिनाम संकीर्तन, भजन, ढोल करताल और जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सियां खींचीं और श्री जगन्नाथ को अपना आरं और श्रद्धा अर्पित की। शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद जुलूस अंबिकापत्ती स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचा, जहां विशेष प्रार्थनाओं, आरती और प्रसाद वितरण के साथ उल्टा रथ यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। भक्तों की आस्था, बहुदा यात्रा में भागीदारी और भगवान जगन्नाथ के दर्शन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं।

लमडिंग में भूमि हस्तांतरण को लेकर उठे सवाल, पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच की मांग तेज

लमडिंग, 24 जुलाई (ख.सं।) होजाई जिले के लंका राजस्व चक्र अंतर्गत लमडिंग मौजा स्थित एक भूमि के हस्तान्तरण से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अध्ययन के बाद स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल उठे हैं। इन अभिलेखों के अनुसार जिस भूमि का नामांतरण पहले रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में दर्ज था, बाद के वर्षों में वही भूमि दो निजी व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दिखाई देती है। इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अब तक किसी सक्षम न्यायालय, जांच एजेंसी अथवा सरकारी विभाग ने इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध कार्य की पुष्टि नहीं की है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार लंका राजस्व चक्र के अंतर्गत जोरंगड़ा गांव

स्थित लगभग 1 बीघा 4 कठा भूमि को 7 फरवरी 2012 को रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तत्कालीन भू-स्वामियों से खरीदा गया था। इसके बाद संबंधित राजस्व प्रक्रिया पूरी करते हुए म्यूटेशन केस संख्या 347/2011-12 के माध्यम से भूमि का नामांतरण कंपनी के पक्ष में दर्ज किया गया। बाद में सामने आए राजस्व अभिलेखों से पता चलता है कि वर्ष 2017 में म्यूटेशन केस संख्या 2232/2017 के तहत उसी भूमि का नामांतरण दो निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ लिया और स्थानीय लोगों के बीच यह जिज्ञासा बढ़ी कि पहले से कंपनी के नाम दर्ज भूमि का बाद में नामांतरण किस प्रक्रिया के तहत किया गया तथा क्या उस समय लागू सभी नियमों और औपचारिकताओं का पालन किया गया था। भूमि कानून से जुड़े जानकारों का कहना है कि नामांतरण केवल राजस्व अभिलेखों



को अद्यतन करने की प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य भूमि कर और प्रशासनिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है। केवल नामांतरण का आधार पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व अंतिम रूप से सिद्ध नहीं होता। भूमि से जुड़े अधिकारों

अथवा दस्तावेजों की वैधता का निर्णय केवल सक्षम न्यायालय या अधिकृत प्राधिकारी ही कर सकता है। रेमेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम पहले भी राज्य में संचालित रूप से सिद्ध नहीं होता। भूमि से जुड़े अधिकारों

में रहा है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी ऐसी कंपनी के नाम दर्ज भूमि का बाद में नामांतरण किया जाता है, तो संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न रहे। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि नामांतरण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप संपन्न हुई थी या नहीं। यदि सभी नियमों का पालन किया गया है, तो जांच से यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी और अनावश्यक कंसी भी भूमि के नामांतरण से पहले आवेदन, पंजीकृत विक्रय बिलेख, सत्यापन रिपोर्ट, वित्तीय गतिविधियों के कारण सार्वजनिक चर्चा

आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। इसलिए इस मामले में भी वास्तविक स्थिति का पता तभी चल सकेगा जब संबंधित मूल सरकारी फाइलों और अभिलेखों की विस्तार से जांच की जाएगी। मामले के दौरान उस समय संबंधित राजस्व कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक चर्चा में आए हैं। लेकिन यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अब तक किसी विभागीय जांच या न्यायिक आदेश में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी या निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी अधिकारी की भूमिका पर अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के नाम बाद के नामांतरण रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनका उल्लेख केवल उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के संदर्भ में किया गया है। इस समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि को प्रभावित करना या उनके खिलाफ कोई आरोप

लगाना नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। भूमि प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि किसी राजस्व अभिलेख को लेकर सार्वजनिक स्तर पर संदेह उत्पन्न होता है, तो प्रशासन द्वारा समय पर उसकी जांच किया जाना अनिवार्य में होता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होता है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू करते हैं, तो घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई थी या फिर किसी स्तर पर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है। भूमि विशेषज्ञों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड केवल प्रशासनिक दस्तावेज होते हैं।

